● वर्ष-3
● अंक-75
रायपुर, रविवार
05 नवंबर 2023
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› बस्तर के नक्सल प्रभावित ...

गरीब अन्न कल्याण योजना अगले 5 वर्षों तक जारी रहेगी

प्रधानमंत्री की विशाल आमसभा, दुर्ग की धरती से देश को मोदी की गारंटी

दुर्ग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्ग की धरती से देश के 80 करोड़ गरीबों को गारंटी दी है कि दिसम्बर में समाप्त हो रही प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना की अवधि अगले 5 साल के लिए बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि हमने यह निश्चय किया है और इसकी गारंटी छत्तीसगढ़ के दुर्ग की पवित्र धरती से दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल ही छत्तीसगढ़ भाजपा ने संकल्प पत्र जारी किया है। इस संकल्प पत्र का एक एक संकल्प तेजी से पूरा किया जाएगा।

दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में आज आयोजित विशाल आमसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरते हुए कहा कि मोदी के लिए देश में केवल एक ही जाति है और वो है गरीब। आज भाजपा की नीतियों की वजह से ही साढ़े तेरह करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। उनका आत्म विश्वास बढ़ा है कि खुद गरीबी देखी पर अब अपने बच्चों को गरीबी नहीं देखने देंगे। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लोग रोज किलो किलो गालियां मोदी को देते है कि कैसे एक ओबीसी वर्ग का आदमी देश का प्रधानमंत्री बन गया। गरीब अन्न कल्याण योजना के बारे में उन्होंने बताया कि यह योजना अगले 5 वर्षो तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यह चुनावी घोषणा नहीं हैं, मोदी की गारंटी है। श्री मोदी ने कहा कि जब तक कांग्रेस केंद्र में रही, गरीबों को लूटती रही पर जब से एक गरीब परिवार का बेटा, आप लोगों के बीच निकला हुआ , गरीबी देखा हुआ आपका भाई , बेटा जिसे आपने ही देश

का प्रधानमंत्री बनाया, उसी ने आपके ही आशीर्वाद से ऐसी नीतियां बनाई कि आज साढ़े तेरह करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके है। भाजपा ने अपना काम बहुत ईमानदारी से किया है। आज देश में गरीब एकजुट होकर मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। मोदी की महासेना में शामिल होकर गरीबी दूर करने निकल रहा है तो राजनीतिक दलों के पेट में दर्द होने लग गया है। ये लोग कैसे कैसे षडयंत्र रच रहे है कि आखिर कैसे गरीब की एकता को तोड़ा जाए, आपस में लड़ाया जाए। ऐसा राजनीतिक ज़हर घोल रहे हैं ।लेकिन मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि हमें मिलकर ऐसी ताकतों से लड़ना है कांग्रेस गरीबों से नफ़रत करती है और चाहती है कि गरीब जीवन भर गरीब ही बना रहे। देश में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की गई है और इसकी रजिस्ट्री घर की महिला के नाम पर होती है। हमारी नीतियां गरीब कल्याण के लिए हैं। हर गरीब को घर मिले , हर घर नल - जल हो , शौचालय हो। यह काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती रहेगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मजदूरी करने लोग एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाते रहते हैं और उनको राशन नहीं मिल पाता था पर अब वन नेशन वन राशन कार्ड से देश भर में कहीं से भी राशन मिल सकता है। आप लोगों के स्वास्थ की चिंता करते हुए आयुष्मान कार्ड की योजना लायी गई हैं। इससे 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मंह किया जाता है। सभी को सस्ती दरों पर दवा उपलब्ध हो सकें, इसके लिए जन औषधि केंद्र खोले गए पर ये भी कांग्रेस को रास नहीं आया और छत्तीसगढ़ में 100 से अधिक औषधि केंद्र बंद करवा दिए।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग के लोगों की भागीदारी है। कांग्रेस पार्टी को यह बताना चाहिए कि आखिर ओबीसी वर्ग से इतनी नफ़रत क्यों है। इनके एक नेता ने तो पूरे ओबीसी समाज को चोर तक कह दिया।

छत्तीसगढ़ के विषय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस की प्राथमिकता प्रारंभ से ही अपनी तिज़ोरी भरना रही है । अपने चहेतों को नौकरी देना रही है। आज पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है 30 टका कक्का आपका काम पक्का। मीडिया में आ रहा है कि कैसे छत्तीसगढ़ में लूट , सट्टा, का पैसा चुनाव में लगाया जा रहा है और इनके तार किससे जुड़े हैं, आप सभी जानते हैं। देश के सुरक्षा बलों पर मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों का हिसाब करने के लिए ही आप सभी ने मुझे दिल्ली भेजा है। आपकी सेवा करने के लिए मुझे चुनकर भेजा है। मेरा आप सभी से वादा है कि जिसने भी आपको लूटा है, उस पर कार्यवाही होगी। वो जेल जाएंगे। पाई पाई का हिसाब होगा । छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने लूट मचाकर छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किया है। दो हजार करोड़ का शराब घोटाला, 500 करोड़ का कोल घोटाला, 1300 करोड़ का गोठान घोटाला, गोबर घोटाला , डीएमएफ में घोटाला , पीएससी में घोटाला। एक भी ऐसा नहीं जिनको इन्होंने लूटा नहीं। कांग्रेस पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबों को लूटती आ रही है।

प्रधानमंत्री मोदी ने आमसभा में उपस्थित जनसमुदाय से अपील करते हुए कहा कि आपने छत्तीसगढ़ में 5 साल कांग्रेस को दिया है। 30 दिन बचे हैं। मुझ पर भरोसा रखो आप सभी को इनसे मुक्ति मिल जाएगी। 3 दिसंबर को भाजपा की सरकार बनते ही आपको मकान मिल जाएगा। आप कमल फूल छाप पर बटन दबाते ही मोदी को मजबूत करेंगे। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की हालत क्या कर दी हैं आप सभी जानते हैं। मलकीत सिंह का क्या गुनाह था भुनेश्वर साहू का क्या गुनाह था ...?प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि रायपुर से विशाखापटनम कारीडोर का निर्माण हो, बस्तर में नया प्लांट स्थापित हुआ। भिलाई इस्पात संयंत्र को अपग्रेड किया, दल्ली राजहरा रेल लाइन का विस्तार हुआ।

विकास के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी: योगी

रायपुर/कवर्धा। भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी विजय शर्मा के पक्ष में प्रचार करने कवर्धा पहुंचे उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय सरदार पटेल मैदान में ऐतिहासिक जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा सौभाग्य है विधानसभा चुनाव के बहाने काशी विश्वनाथ की धरती उत्तरप्रदेश से छोटी काशी कहा जाने वाला धर्मनगरी कवर्धा आने का मौका मिला। छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम का ननिहाल है। उन्होंने कहा छोटी सी गलती से कितना नुकसान कर देती है, भगवा ध्वज के सम्मान करने वाले राम भक्तों को लाठी से पीठा जाता है। लव जिहाद का विरोध करने वाला छोटा सा कार्यकर्ता उसकी हत्या कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है वहां लव जेहाद,धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया गया है। अब कोई अवैध धर्मांतरण यूपी में नही कर सकता और करेगा तो खामियाजा भी भुगतेगा। छोटी से गलती से नुकसान होता है अन्नदाता किसानो का, युवाओं का, बहन बेटिओं का और धार्मिक पर्व का सब का नुकसान हो जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अटल बिहारी जी के सपने के अनुरूप पिछले 15 वर्षो तक छत्तीसगढ़ का विकास हो हुआ। कांग्रेस ने अपने संस्कारो के अनुरूप छत्तीसगढ़ के विकास को पूरी तरह बाधित कर दिया। कवर्धा हमारे लिए काशी जैसा पवित्र है कांग्रेस ने यहाँ अकबर जैसे व्यक्ति को बैठा दिया। आपकी आस्था से खिलवाड़ करने ऐसे व्यक्ति को बैठाया गया है जिसे आपके आस्था से कोई मतलब नही, जिसके संरक्षण में हम सबकी आत्मा भगवा ध्वज को पैरो से कुचला जाता है। उन्होंने साजा की घटना का जिक्र करते हुए कहा यदि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार होती तो क्या कोई ऐसा हिम्मत करता। क्या एक गरीब भुवनेश्वर साहू की हत्या कर देता, क्या अपराधी खुलेआम घूमता। उन्होंने कहा कि साजा के भुवनेश्वर साहू के पिता जी ने बड़ा हिम्मत का परिचय दिया किसी और के साथ ऐसा न हो इसलिए स्वयं मैदान में आ गए है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाकर एक अच्छे कार्यकर्ता का मान बढाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये केवल चुनाव की लड़ाई नहीं अपने अस्तित्व की लडाई है, आप सबके अस्तित्व की लड़ाई है। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में भारत बुलंदियों के नई ऊँचाइयों को छुता हुआ आगे बढ़ रहा है। विकास का व्यापक रोड मैप मोदी जी ने बनाया उसे छत्तीसगढ़ में सही ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है। मोदी जी के विकास के बनाये रोड मैप को सही ढंग से जमीन में उतारना है तो मोदी जी के साथ डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाइये। मोदी जी घोषणा पत्र के माध्यम से जो गारंटी दी है वह 100 प्रतिशत की गारंटी वाला घोषणा है जो पूरा होना ही होना है।

प्रमुख समाचार

19 नवंबर को एयर इंडिया से यात्रा न करें, खालिस्तानी आतंकी की धमकी

नईदिल्ली। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नून का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें वह 19 नवंबर को एयर इंडिया से यात्रा करने की योजना बना रहे लोगों को धमकी देते हुए कह रहा है कि उनकी जान खतरे में होगी। पन्नून ने

वीडियो में कहा कि हम सिख लोगों से 19 नवंबर को एयर इंडिया से यात्रा न करने के लिए कह रहे हैं। वैश्विक नाकाबंदी होगी। 19 नवंबर को एयर इंडिया से यात्रा न करें नहीं तो आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी। पन्नून ने आगे दावा किया कि दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 19 नवंबर को बंद रहेगा और इसका नाम बदल दिया जाएगा।खालिस्तानी आतंकवादी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह वही दिन है जिस दिन चल रहे क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच होगा। 10 अक्टूबर को, पन्नून अमेरिका स्थित प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस संगठन का प्रमुख है। उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजरायल-फिलिस्तीन युद्ध से सीखने की धमकी दी थी, ताकि भारत में भी इसी तरह की प्रतिक्रिया न हो। अमृतसर में जन्मे पन्नून 2019 से राष्ट्रीय जांच एजेंसी के स्कैनर पर हैं, जब जांच एजेंसी ने उनके खिलाफ अपना पहला मामला दर्ज किया था। उन पर आतंकवादी कृत्यों और गतिविधियों की वकालत करने और उन्हें संचालित करने में प्राथमिक भूमिका निभाने और अपनी धमकियों और डराने-धमकाने की रणनीतियों के माध्यम से पंजाब और भारत के अन्य हिस्सों में भय और आतंक फैलाने का आरोप लगाया गया है।

कांग्रेस भ्रष्टाचार, कमीशन, दंगे, के फॉर्मूले पर चल रही है: अमित शाह

नईदिल्ली। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार (4 नवंबर) को लोगों से आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट देने का आग्रह करते हुए कहा कि पार्टी ने अपने 18 साल के शासन में सभी समुदायों

के कल्याण के लिए काम किया और इसे एक मजबूत राज्य बनाया। अमित शाह ने कहा कि बेमिसाल राज्य जबकि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। उन्होंने कांग्रेस पर अपना खजाना भरने के लिए काम करने का आरोप लगाया और कहा कि इसके विपरीत, भाजपा ने राज्य का विकास किया है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। शाह, जिन्होंने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी का दौरा किया, ने एक चुनाव अभियान को संबोधित किया और राज्य में अपने पिछले शासन के लिए कांग्रेस की आलोचना की और आरोप लगाया कि पार्टी ने अपने लाभ के लिए काम किया। शाह ने कहा कांग्रेस पार्टी 4ष्ट फॉर्मूले पर चलती है- ष्ट- भ्रष्टाचार, ष्ट- कमीशन, ष्ट- सांप्रदायिक दंगे, ष्ट- आपराधिक राजनीति। मध्य प्रदेश को इन 4ष्ट से बचाने और विकास की धारा में लाने के लिए बीजेपी को वोट देना बहुत जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि ...कांग्रेस ने जब भी शासन किया, केवल अपना खजाना भरने का काम किया। जबकि भाजपा ने विकास के लिए काम किया। आज मैं कमलनाथ से कहने आया हूं कि अगर उनमें थोड़ी भी हिम्मत है तो जवाब दें - जब उन्होंने 2002 में मध्य प्रदेश छोड़ा था।

चंद्रयान-2 कैसे फेल हुआ, इसरो के अध्यक्ष के किताब पर हंगामा

नईदिल्ली। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने शनिवार को कहा कि किसी संगठन में शीर्ष पद तक पहुंचने की यात्रा के दौरान प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी तरह की चुनौतियों से गुजरना पड़ता है और उन्होंने भी जीवन में ऐसी

कठिनाइयों का सामना किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अंतरिक्ष एजेंसी में अपनी दशकों लंबी यात्रा के दौरान सामना की गई कुछ चुनौतियों का उल्लेख अपनी आगामी आत्मकथा निलावु कुदिचा सिम्हंगल में किया है। उन्होंने कहा कि लेकिन यह किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। सोमनाथ उस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें दावा किया गया था कि उनकी आत्मकथा में उनके पूर्ववर्ती के सिवन के बारे में कुछ आलोचनात्मक टिप्पणियाँ हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रमुख पदों पर रहने वाले व्यक्तियों को कई चुनौतियों से गुजरना पड़ सकता है। उनमें से एक संगठन में पद पाने के संबंध में चुनौतियां हैं। ये ऐसी चुनौतियाँ हैं जिनसे हर किसी को गुजरना पड़ता है। उन्होंने बताया कि अधिक व्यक्ति एक महत्वपूर्ण पद के लिए पात्र हो सकते हैं। मैंने बस उस विशेष बिंदु को सामने लाने की कोशिश की। मैंने इस संबंध में किसी विशेष व्यक्ति को लक्षित नहीं किया।

अडानी का प्रोजेक्ट कांग्रेस ने किया रिजेक्ट: राहुल

बस्तर में गरजे राहुल गांधी

जगदलपुर। बस्तर में कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी और उनके उद्योगपति मित्र अडानी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी के सबसे बड़े मित्र अडानी का बस्तर में आयरन ओर का एक प्रोजेक्ट था जिसे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कैंसल करके दिखा दिया। क्योंकि हमारे आदिवासी भाइयों ने कहा कि हमें वो प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। हमने आपकी आवाज का आदर करते हुए प्रोजेक्ट को निरस्त कर दिया।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों से किया हर वादा निभाया है। हम ट्राइबल बिल लाए, पेसा कानून लाए, जमीन अधिग्रहण बिल लाए जिसमें साफ लिखा था कि ग्राम सभा इजाजत नहीं देगी तब तक कोई भी आदिवासियों की जमीन नहीं ले सकता है। हमने कहा था कि अगर 5 साल के अंदर किसी भी उद्योगपति ने अपना उद्योग शुरू नहीं किया तो आदिवासियों को उनकी जमीन वापिस की जाएगी। हमने ये वादा किया था जिसे निभाया भी।

वनवासी शब्द का प्रयोग पीएम मोदी जी करते है। वनवासी शब्द का इस्तेमाल करने वाले सोचते हैं कि जंगल में जो जानवर रहते हैं वैसी आपकी जगह होनी चाहिए। जैसे इनके नेता जानवरों से बर्ताव करते हैं। इनके दिमाग में आप लोग जंगल के हो। भाजपा आदिवासी शब्द का इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया।

चुनावी रियायतों की कीमत

आज भी नेपथ्य में हैं कई नीतिगत सवाल

नईदिल्ली। भारत के राजनीतिक परिदृश्य में सत्ता की चाबी चुनावी रियायतों में होती है। सत्ताओं द्वारा जनता के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करने का नया उपकरण नकद हस्तांतरण है। इन सर्दियों में जिन पांच राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें से चार अपेक्षाकृत कम औद्योगीकृत और ज्यादा आबादी वाले हैं। सभी राजनीतिक दल रोजगार, बिजली, सड़क, पानी और विकास की बात करते ही हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि अब चुनाव प्रतिस्पर्धी वादों, मुफ्त उपहारों और नकद हस्तांतरण की प्रतियोगिता बनकर रह गए हैं। महिला मतदाता इसमें गेम चेंजर बनकर उभरी हैं, जिन्हें आकर्षित करने के लिए राजनीतिक दलों में लोक-लुभावन वादे करने की होड़ दिख रही है। अब मध्य प्रदेश को ही लीजिए, जहां कांग्रेस द्वारा महिलाओं को डेढ़ हजार रुपये देने के वादे के बाद शिवराज चौहान सरकार ने लाड़ली बहना योजना के तहत नकद हस्तांतरण को एक हजार से बढ़ाकर डेढ़ हजार रुपये कर दिया है और इसे तीन हजार रुपये महीना तक बढ़ाने का वादा भी किया है। वहीं, राजस्थान की गहलोत सरकार ने महिलाओं को दस हजार रुपये सालाना भत्ता देने का वादा किया है। तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव ने पात्र परिवारों की महिलाओं को तीन हजार रुपये प्रति माह देने का वायदा किया है। मतदाताओं को लुभाने की एक टॉप-अप रणनीति भी है। इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा पहले से चलाई जा रही योजनाओं को राज्यों द्वारा पैसा उपलब्ध कराया जाता है। भारत में कृषि में लगी हुई 45 फीसदी से ज्यादा आबादी भी, जो राष्ट्रीय आय के छठे हिस्से पर जीवन-यापन करने को मजबूर है, राजनीतिक दलों के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र है, जहां के मतदाताओं को लुभाना राजनीतिक दल अपना कर्तव्य समझते हैं।

2018 में तेलंगाना और ओडिशा ने रायथु बंधु और कालिया नामक योजनाओं के तहत किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास किए। इस विचार को राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तौर पर अपनाया गया, जिससे किसानों को छह हजार रुपये मिलते हैं। आंकड़ों से मुआवजा बढ़ाने की राजनीतिक मजबूरी स्पष्ट होती है। 15 से ज्यादा राज्यों के आधे से ज्यादा परिवार कृषि पर निर्भर हैं।

कांग्रेस ने रायथु बंधु भुगतान को 15 हजार तक बढ़ाने का और खेतिहर मजदूरों के लिए 12 हजार रुपये देने का वादा किया। अब केसीआर कहां पीछे रहने वाली थी? उसने रायथु बंधु भुगतान को बढ़ाकर 16 हजार रुपये वार्षिक कर दिया। महाराष्ट्र में भी पात्र किसानों को छह हजार रुपये का अतिरिक्त भुगतान करने के लिए नमो शेतकारी महासम्मान नामक एक टॉप-अप योजना शुरू की गई है।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय भुगतान निगम पोर्टल पर राज्यों द्वारा सात हजार से अधिक कोड के रजिस्ट्रेशन के साथ नकद हस्तांतरण का विस्तार दिखता है। इसमें उन योजनाओं के लिए भुगतान शामिल है, जो केंद्र द्वारा शुरू, लेकिन राज्यों द्वारा प्रशासित होती हैं। इसके अलावा, राज्यों द्वारा अतिरिक्त सब्सिडी वाली केंद्र की योजनाएं और राज्यों द्वारा शुरू की गई योजनाएं भी शामिल हैं। इस वर्ष की शुरुआत में केंद्र सरकार ने रसोई गैस की कीमतों में 200 रुपये की कटौती की थी। चुनावी राज्यों में में भी रसोई गैस सिलिंडर पर सब्सिडी बढ़ाई गई है। राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में सिलिंडर क्रमशः 500, 400 और 450 रुपये में दिए जा रहे हैं।

मई 2023 में मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों द्वारा सहकारी समितियों से लिए गए ऋण पर ब्याज माफ करने का फैसला किया था। राज्य सरकार ने क्रेडिट सोसाइटियों के लिए गए दो लाख रुपये तक के ऋण पर देय ब्याज का भुगतान करने का वादा भी किया। इस योजना से करीब 11 लाख से ज्यादा किसानों को राहत मिलने की उम्मीद थी। जुलाई में कांग्रेस ने वादा किया कि अगर वह सत्ता में आती है, तो अपने कार्यकाल के दौरान घोषित ऋण माफी को फिर से शुरू करेगी। आश्चर्य है कि राजनीतिक दल जो वादे करते हैं, उनकी क्या लागत होगी, इस पर विचार करने की वे जरूरत भी नहीं समझते।

चुनावी वादों को पूरा करने की चुनौती राज्यों के बजट में झलकती है। मिसाल के तौर पर कर्नाटक को चुनाव से पहले जारी अपनी एक गारंटी के लिए 52 हजार करोड़ रुपये अलग से रखने पड़े। हालांकि राजनीतिक दलों को इसकी चिंता नहीं दिखती। खर्च करने की इच्छा और खर्च में बढ़ोतरी शायद वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) के संग्रह में लगातार वृद्धि से हुई है। वार्षिक जीएसटी राजस्व संग्रह 2017-18 के 7.18 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 18.10 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है। 2023-24 की पहली छमाही के लिए संग्रह 11 फीसदी बढ़कर 9.92 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो औसतन लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपये प्रति माह है।दरअसल, इस साल की पहली छमाही में राज्यों का जीएसटी राजस्व 2022-23 के 3.68 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 4.22 लाख करोड़ रुपये रहा। धन के लिए दूसरा रास्ता राज्यों द्वारा ईंधन पर लगाया जाने वाला कर है, जिससे ?राज्यों ने पिछले साल 3.2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का संग्रह किया।

कोरबा जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में 51 अभ्यर्थी मैदान में, आबंटित हुए प्रतीक चिन्ह

रामपुर से 9, कोरबा 19, कटघोरा 14 एवं पाली-तानाखार से 9 अभ्यर्थी आजमाएंगे अपनी किस्मत

कोरबा। विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु कोरबा जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों हेतु नाम वापसी पश्चात कुल 51 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में हैं। विधानसभा रामपुर से 09 कोरबा से 18 कटघोरा से 14 एवं विधानसभा पाली-तानाखार से 09 अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे।

अभ्यर्थियों को संबंधित रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्रतीक चिन्ह भी आबंटित किए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा क्षेत्रवार निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थी, पार्टी का नाम एवं उन्हें आबंटित प्रतीक चिन्ह का विवरण इस प्रकार है-

विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 20 रामपुर- श्री जगत राम राठिया-बहुजन समाज पार्टी-हाथी, श्री ननकी राम कंवर- भारतीय जनता पार्टी-कमल, श्री फूल सिंह राठिया-इंडियन नेशनल कांग्रेस-हाथ, श्री बालमुकुंद राठिया-जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़(जे)-वर्ग में हल जोतता किसान, श्री अलेक्जेंडर टोप्पो-जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी-छड़ी, कन्हैया आनंद कंवर-हमर राज पार्टी-बाल्टी, श्री बिरेश्वर कंवर- निर्दलीय-स्पैनर, श्री धनवार वेदलाल वनवासी- निर्दलीय-बैटरी टॉर्च, श्री रामदयाल उरांव -निर्दलीय-ट्रक।

विधानसभा क्षेत्र क्र. 21 कोरबा- श्री जयसिंह अग्रवाल-इंडियन नेशनल कांग्रेस-हाथ, श्री धनंजय सिंह चंद्रा-बहुजन समाज पार्टी-हाथी, श्री पुरन लाल साहू-जनता कॉंग्रेस छत्तीसगढ- वर्ग में हल जोतता किसान, श्री लखनलाल देवांगन-भारतीय जनता पार्टी-

कमल, श्री इंजीनियर विशाल केलकर-आम आदमी पार्टी-झाड़ू, अब्दुल नफीश खान 'अधिवक्ता'-गणा सुरक्षा पार्टी-बैटरी टॉर्च, श्री मदन लाल चंद्रा-बलीराजा पार्टी-गैस सिलेण्डर, श्री योगेश साहू-पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया(डेमोक्रेटिक)- स्कूल का बस्ता, श्री रणबीर आदिले-जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी-छड़ी, श्री राजकुमार दुबे-लोक जन शक्ति पार्टी(राम विलास)-हेलीकॉप्टर, श्री सुनील कुमार तायल-भारतीय शक्ति चेतना पार्टी-बांसुरी, श्री सुनील सिंह-कम्युनिस्ट पार्टी ऑफइंडिया-बाल और हंसिया, श्री राजेश कुमार पांडेय-निर्दलीय-कांच का गिलास, श्री घनश्याम चंद्रा गांधी-निर्दलीय-माचिस की डिब्बी, श्री लखन लाल देवांगन-निर्दलीय-पानी का जहाज, श्री प्रवीण मसीह-निर्दलीय-एयरकंडीस्नर, श्री मिर्जा मुस्ताक अहमद-निर्दलीय-फुटबॉल, श्री अंकित अग्रवाल-निर्दलीय-बल्ला तथा श्री सिमॉन फ्रान्सीश-निर्दलीय-बल्लेबाज।

विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-22 कटघोरा-श्री चंद्रकांत डिक्सेना-आम आदमी पार्टी-झाड़ू, श्री जवाहर सिंह कंवर-कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्कसिस्ट)-हथोड़ा, हंसिया, सितारा, श्री पुरुषोत्तम कंवर-इंडियन नेशनल कांग्रेस-हाथ, श्री प्रेमचंद पटेल-भारतीय जनता पार्टी-कमल, श्री इंजीनियर सत्यजीत कुर्रे-बहुजन समाज पार्टी-हाथी, श्री सपुरन कुलदीप- जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे)-वर्ग में हल जोतता किसान, श्री कल्याण सिंह तंवर- छत्तीसगढ़िया पार्टी-गैस सिलेण्डर, श्री दिलीप कंवर (डी. के. सरजाल)-आम्बेडकराईट पार्टी ऑफ इंडिया-कोट, श्री भुवनेश्वर सिंह श्रोते-गोंडवाना गणतंत्र पार्टी-आरी, श्री मिलन दास दीवान-गणा सुरक्षा पार्टी-बैटरी टॉर्च, श्री सुरेंद्र राठौर (सोनू भैया)-जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी-छड़ी, श्री रविन्द्र महंत-निर्दलीय-कांच का गिलास, श्री अजय सिंह-निर्दलीय-हॉकी और बॉल, श्री सुदामा राम-निर्दलीय-बांसुरी।

विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 23 पाली-तानाखार- श्री उइके रामदयाल -भारतीय जनता पार्टी-कमल, श्री छत्रपाल सिंह कंवर- जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे)-वर्ग में हल जोतता किसान, श्रीमती दुलेश्वरी सिदार-इंडियन नेशनल कांग्रेस-हाथ, श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम-गोंडवाना गणतंत्र पार्टी-आरी,, श्री देवराज सिंह मरकाम-छत्तीसगढ़िया पार्टी-गैस सिलेण्डर, श्री बाबू सिंह कंवर- निर्दलीय-चारपाई, श्री छवि राज-निर्दलीय-बैटरी टॉर्च, श्री आनंद कुमार तंवर-निर्दलीय-टीलर, श्री शिवरात पैकरा (कंवर)-निर्दलीय-छड़ी।

पांच अभ्यर्थियों ने लिया नाम वापस -

विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत जिले के चारों विधानसभा से कुल पांच अभ्यर्थियों ने अपना नाम वापिस लिया। इनमें विधानसभा क्षेत्र रामपुर से श्रीमती सुनीता देवी कंवर-निर्दलीय, कोरबा से श्री सेवक राम अंचल (अंचल भैया)-निर्दलीय, श्री रज्जाक अली-निर्दलीय, श्री शेरे हक़-निर्दलीय और कटघोरा से श्री रवि कुमार रजक-निर्दलीय शामिल हैं।

निर्वाचन व्यय लेखा 06, 10 और 14 को प्रस्तुत करने के निर्देश

विधानसभा निर्वाचन 2023 आयोग के निर्देशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के आज्ञापक प्रावधानों के अंतर्गत कोरबा जिले के विधानसभा निर्वाचन हेतु घोषित अभ्यर्थियों को दस्तोवज के साथ 06, 10 एवं 14 नवंबर को व्यय लेखा के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है। नोडल अधिकारी व्यय लेखा श्री सरोज महिलांगे ने बताया कि उक्त तिथि को विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 20 रामपुर, विधानसभा क्रमांक 21 कोरबा, विधानसभा क्रमांक 22 कटघोरा और विधानसभा क्रमांक 23 पाली-तानाखार के अंतर्गत सभी अभ्यर्थियों के व्यय लेखा की जांच की जाएगी। अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि में सामान्य निर्वाचन कार्यालय कोरबा के निर्धारित कक्ष व्यय लेखा शाखा में दस्तावेज के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।

स्ट्रांग रूम में रखे ईव्हीएम की सुरक्षा के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सौरभ कुमार ने झगरहा स्थित आईटी कॉलेज कोरबा में निर्मित स्ट्रांग रूम में रखे ईव्हीएम मशीन की सुरक्षा हेतु संयुक्त कलेक्टर श्री सेवाराम दीवान को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। साथ ही उनकी सहायता के लिए अन्य कर्मचारियों की भी विभिन्न पालियों में ड्यूटी निर्धारित की गई है।

सहायक कर्मचारियों के अंतर्गत श्री दीपेश यादव सहायक ग्रेड-03 हायर सेकेण्डरी स्कूल कोरकोमा की ड्यूटी सुबह 06 बजे से दोपहर 02 बजे तक, श्री आलोक पाणिग्रही सहायक ग्रेड-03 शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुदुरमाल की ड्यूटी दोपहर 02 बजे से रात्रि 10 बजे तक, श्री विजय आदिले सहायक ग्रेड-03 बालक हायर सेकेण्डरी स्कूल बाल्को की ड्यूटी रात्रि 10 बजे से सुबह 06 बजे तक तथा श्री संदीप भारद्वाज सहायक ग्रेड-03 शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उरगा की ड्यूटी रात्रि 10 बजे से सुबह 06 तक के लिए निर्धारित की गई है।

प्रेक्षकों ने मतदान केन्द्रों, जांच नाको का अवलोकन किया

■ प्रेक्षक सी. के. जमातिया, प्रियतु मण्डल सहित व्यय और पुलिस प्रेक्षक जिले में कर रहे भ्रमण

कोरबा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु कोरबा जिले के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक सहित व्यय और पुलिस प्रेक्षक कोरबा जिले में मतदान केंद्र, स्थैतिक निगरानी दल-चेकपोस्ट आदि का अवलोकन कर रहे हैं। वे ग्रामीणों से मुलाकात कर शत-प्रतिशत् मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी कड़ी में पाली-तानाखार तथा कटघोरा विधानसभा हेतु नियुक्त प्रेक्षक आई.ए.एस. श्री सी.के.जमातिया ने पाली-तानाखार विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया। प्रेक्षक श्री जमातिया ने मतदान केंद्र क्रमांक 178 प्राथमिक शाला सिंघिया, प्राथमिक शाला तुमान मतदान केंद्र क्रमांक 120, प्राथमिक शाला बरबसपुर मतदान केंद्र क्रमांक 141, कटोरी

नगोई मतदान केंद्र क्रमांक 91, मतदान केंद्र क्रमांक 88 जटगा, मतदान क्रेंद्र क्रमांक 01 अमझर, मतदान क्रेंद्र क्रमांक 35-36 पोड़ीकला का निरीक्षण किया। प्रेक्षक ने पोड़ीकला मतदान केंद्र में रैम्प तथा लाईट की व्यवस्था के निर्देश दिए। व्यय प्रेक्षक श्री ओर.एन हरिप्रसाद राव ने स्थैतिक निगरानी दल मोरगा चेकपोस्ट तथा शिकायत कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया तथा पुलिस आब्जर्वर द्वारा बगदेवा में स्थैतिक निगरानी दल चेकपोस्ट नाका की जांच की गई। उन्होंने मतदान केन्द्रों में मतदाताओं की जानकारी हेतु किए गये दीवाल लेखन, दिव्यांग मतदाताओं हेतु बनाये गये रैम्प तथा मतदान केन्द्रों में उपलब्ध अन्य सुविधाओं का निरीक्षण किया और मतदान केन्द्रों में आवश्यकतानुसार सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान संबंधित बूथ लेबल अधिकारी उपस्थित थे। प्रेक्षक ने स्थैतिक निगरानी दल द्वारा चेकपोस्ट के माध्यम से की जा रही जांच का भी अवलोकन किया। इसी तरह कोरबा और रामपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रेक्षक श्री प्रियतु मण्डल ने रामपुर विधानसभा क्षेत्र के कोटमेर, बरपाली सहित अन्य ग्रामों का दौरा किया। उन्होंने मतदान केंद्र का अवलोकन करने के साथ ही ग्रामीणों से मिलकर उन्हें मतदान हेतु प्रेरित किया।

राजनांदगांव में शांतिपूर्ण चुनाव कराने निकाला फ्लैग मार्च

राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले में 7 नवंबर को चुनाव होना है। शांतिपूर्ण और शत प्रतिशत मतदान को लेकर प्रशासन एक तरफ लोगों को जागरूक रहा है तो दूसरी तरफ पुलिस फ्लैग मार्च निकालकर सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर रही है।

राजनांदगांव जिले की चार विधानसभा सीटों राजनांदगांव, डोंगरगढ़, डोंगरगांव और खुज्जी में 7 नवंबर को पहले चरण में चुनाव होगा। चुनाव संपन्न कराने के लिए जिले में अर्धसैनिक बलों की 44 बटालियन पहुंची हुई है। जिसके जरिए शांति और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच मतदान कराया जाएगा। जिला बल के 1000 से ज्यादा पुलिस जवानों को भी मतदान ड्यूटी पर चप्पे-चप्पे में तैनात किया गया है।

शुक्रवार शाम पुलिस विभाग की तरफ से शहर में अर्धसैनिक बलों और जिला पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च में राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग और जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह ने भी पैदल मार्च करते हुए मतदाताओं को शांति और सुरक्षा का संदेश देते हुए भयमुक्त और निष्पक्ष मतदान करने की अपील की। मतदाताओं में जागरूकता लाने शहर के म्युनिसिपल स्कूल मैदान में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और स्कूली छात्र छात्राएं शामिल हुए और लोगों से शत प्रतिशत वोट करने की अपील की।

नक्सलियों ने कांकेर में छत्तीसगढ़ चुनाव का किया बहिष्कार! बैनर लगाए, पर्चे फेंके

कांकेर। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पहले चरण के मतदान से पहले नक्सलियों ने एक बार फिर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। उत्तर बस्तर के कांकेर जिले के कई जगहों पर नक्सलियों ने पर्चे फेंककर और बैनर लगाकर दहशत फैलाने की कोशिश की है।

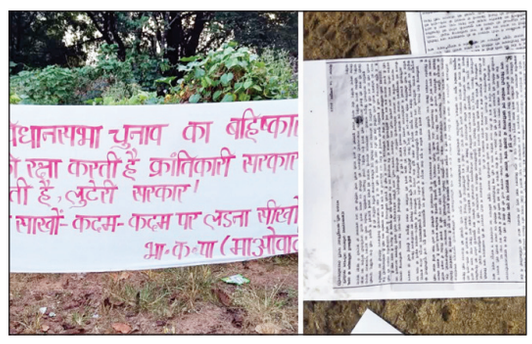

कांकेर जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूरी पर नक्सलियों ने बैनर बांध कर दहशत फैलाने की कौशिश की है। कोयलीबेड़ा मुख्य मार्ग पर ग्राम पंचायत देवरी के साप्ताहिक बाजार स्थल में नक्सलियों ने बैनर बांधा है। कुए माड़ एरिया कमेटी के द्वारा यह बैनर बांधा गया है। बैनर में चुनाव बहिष्कार की बात कही गई है। जिला मुख्यालय के इतने नजदीक नक्सलियों की उपस्थिति पर सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बाद भी नक्सली कांकेर के इतनी नजदीक बैनर बांध कर चले गए।रावघाट एरिया कमेटी के द्वारा यह बैनर बांधा गया है।

अंतागढ़ विधानसभा अंतर्गत आमाबेड़ा से नागरबेडा मार्ग में नक्सलियों ने पर्चे फेंके है। पर्चे में चुनाव बहिष्कार करने की बात लिखी है। जनताना सरकार को बचाने और मजबूत वोट मांगने वाले राजनीतिक पार्टियों को कटघरे में खड़ा कर सजा देने की बात लिखी। कांकेर पुलिस अधीक्षक ने कहा नक्सली लोकतंत्र विरोधी है। चुनाव में खलल और दहशत फैलाने ऐसे कृत्यों को अंजाम देते है। हमारे सुरक्षा बल लगातार क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं। भय मुक्त वातावरण में मतदान करिए।

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश की पुलिस अलर्ट मोड पर है। नक्सली चुनावी माहौल को बिगाड़ने की फिराक में रहते हैं। चुनाव से पहले बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश नक्सली करते हैं। कांकेर जिले में 727 मतदान केंद्रों में 285 संवेदनशील मतदान केंद्र है। जिसमे अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक संवेदनशील मतदान केंद्र है। इस क्षेत्र के मतदान केंद्रों को सुरक्षा की दृष्टि से शिफ्ट किया जाता है। यहां तक मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर से भी भेजा जाता है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

डबल इंजन की सरकार होने से विकास तीव्र गति से होगा: योगी

राजनांदगांव। उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डोंगरगढ़ में जनसभा को संबोधित करते खुज्जी विधानसभा की भाजपा प्रत्याशी गीता साहू और डोंगरगांव के प्रत्याशी भरत वर्मा के पक्ष में वोट देने का आह्वान किया। इस दौरान योगी ने कहा कि केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी तो छत्तीसगढ़ का विकास तीव्र गति से होगा। जनसभा को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि छत्तीसगढ़ जनता अब तक मौजूदा कांग्रेस सरकार के कार्यशैली से नाखुश रही है और कल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ का घोषणा पत्र जारी किया और इसमें किए गए सभी वादों को भाजपा शत-प्रतिशत पूरा करेगी। योगी आदित्यनाथ के समर्थन में जनसभा में उपस्थित लोगों ने जयश्री राम के नारे लगाए गए। इस अवसर पर भाजपा नीलू शर्मा, दिनेश गांधी, प्रदीप गांधी, लक्ष्मीनारायण गुप्ता, भाजपा प्रत्याशी गीता साहू और डोंगरगांव के प्रत्याशी भरत वर्मा समेत अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे।

घोटाले की जांच पूरी करो नहीं तो चुनाव बहिष्कार

जांजगीर चांपा। अकलतरा विकास खंड के दल्हा पोड़ी गांव के लोगों ने चुनाव बहिष्कार की धमकी दी है। ग्रामीणों ने अपने गांव में जुलूस निकालकर मतदान नहीं करने की मुनादी भी करा दी है। ग्रामीण अपने गांव के सरपंच और सचिव से परेशान है।ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच और सचिव ने मिलकर लाखों रुपए का घोटाला किया है।जिसकी जांच नहीं की जा रही है। घोटाले की जांच के लिए दो साल पहले शिकायत भी की गई थी। लेकिन जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों के चुनाव बहिष्कार करने की घोषणा के बाद जनपद सीईओ ने आधी अधूरी जांच कर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ग्रामीणों ने पारदर्शिता के साथ जांच नहीं होने पर गांव में प्रचार के लिए प्रत्याशियों को भी प्रवेश नहीं करने की हिदायत दी है। आपको बता दें कि दल्हा पोड़ी शंकर गांव में 20 वार्ड है। 5 हजार के करीब मतदाता हैं। ग्रामीणों के मुताबिक चुनाव बहिष्कार की घोषणा के बाद जनपद पंचायत ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था।

अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर हुई कार्यवाही

कोरबा। कलेक्टर सौरभ कुमार के निर्देशन में जिले में खनिज विभाग द्वारा गौण खनिज आधारित क्षेत्रों से रेत के अवैध परिवहन, उत्खनन एवं भंडारण पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इस हेतु जिले के नगरीय निकाय सहित ग्रामीण क्षेत्रों पर खनिज अमलो की तैनाती कर नियमित कार्यवाही की जा रही है। खनिज अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार गौण खनिज रेत की रायल्टी की चोरी की रोकथाम हेतु विभाग के अमला द्वारा कसरेंगा, कटघोरा, उरगा, कुसमुंडा, कुरुडीह, भैंसामुंडा, बरमपुर, ईमलीडुग्गु, भिलाईखुर्द, भैंसमा, अकलतरा आदि स्थानों से अक्टूबर 2023 माह में 36 प्रकरण दर्ज किया गया है। जिसके अंतर्गत गौण खनिज रेत के 29 प्रकरण दर्ज कर कुल 3 लाख 85 हजार 324 रुपए अर्थदंड वसूल किया गया है एवं शेष प्रकरणों में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त प्रकरणों में वाहनों को जब्त कर छत्तीसगढ़ गौण खनिज के विभिन्न अधिनियमों अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है।

वाहनों की सघन जांच के दौरान 01 लाख 50 हजार रूपए के कपड़े जब्त

कांकेर। विधानसभा निर्वाचन के दौरान जिले के सभी रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, एसएसटी (स्थैतिक निगरानी दल) एवं एफएसटी (उड़नदस्ता दल) द्वारा वाहनों की निगरानी करते हुए लगातार जांच की जा रही है। इसी क्रम में सिंगारभाट स्थित चेक पोस्ट में दोनों ओर से आने जाने वाली वाहनों की गहन जांच की गई। इस दौरान कपड़ों से भरी एक गाड़ी जब्त की गई, जिसमें 50 हजार रुपए की 64 स्वेटर, 70 हजार रुपए की 35 जैकेट एवं 30 हजार रुपए की 8 कोट सहित कुल 107 सामान जब्त किया गया। जब्त की गई कपड़ों की कुल अनुमानित लागत 01 लाख 50 हजार रुपए बताया गया। जांच के दौरान मौके पर नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी एवं एसएसटी दल प्रभारी उपस्थित थे। जब्ती की कार्यवाही कर थाना प्रभारी को सुपुर्द किया गया।

सभी प्रत्याशी के व्यय लेखा का प्रथम जांच होगा 6 को

सारंगढ़। विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत विधानसभा सारंगढ़-17 और बिलाईगढ़-43 के सभी अभ्यर्थियों के व्यय लेखा का मिलान और प्रेक्षक के समक्ष प्रथम जांच 06 नवंबर 2023 को कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सारंगढ़ में प्रात: 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ ने पत्र जारी कर कहा है कि सभी प्रत्याशी निर्धारित तिथि 06 नवंबर 2023 को प्रथम जांच, 10 नवंबर 2023 को द्वितीय जांच और 15 नवंबर 2023 को तृतीय जांच के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपने समस्त दस्तावेजों के साथ उपस्थिति देना सुनिश्चित करें।

प्रतापपुर में 38 सालों से दोबारा रिपीट नहीं हुई कोई भी पार्टी

सरगुजा। छतीसगढ़ के सरगुजा संभाग में एक ऐसी विधानसभा सीट है, जहां से पिछले 38 सालों से लगातार कोई एक पार्टी जीत हासिल नहीं कर पाई है। अगर एक बार बीजेपी यहां से जीत दर्ज की है तो दूसरी बार कांग्रेस को जीत मिलती है। यहां की जनता एक बार भाजपा तो एक बार कांग्रेस को मौका देती है। क्षेत्र के विकास के दृष्टिकोण से लोगों के हित में यहां मतदान होता है।यही कारण है कि जीतने वाले प्रत्याशी अगली बार दोबारा जीत के बारे में नहीं सोचते।

सूरजपुर जिले की प्रतापपुर विधानसभा का आधा हिस्सा सूरजपुर तो आधा हिस्सा बलरामपुर जिले में पड़ता है। यह उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा विधानसभा क्षेत्र है। यह सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। यह सीट पहले पिलखा के नाम से जानी जाती थी। परिसीमन के बाद साल

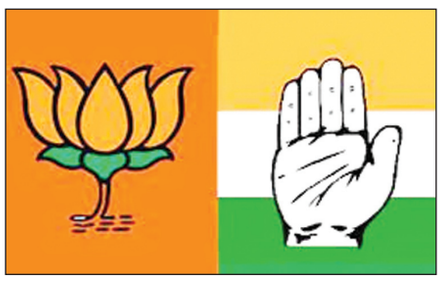

1985 में इसे प्रतापपुर विधानसभा बना दिया गया। यहां से प्रेम साय सिंह एक ऐसे नेता हैं जो दो बार जीत दर्ज कर चुके हैं। बाकी के चुनावों में उनको भी हार का सामना करना पड़ा है।

मीडिया से पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुधीर पांडे ने बताया कि साल 1977 में ये सीट अस्तित्व में आई। पिलखा विधानभसा से पहले विधायक जनता पार्टी के नर नारायण सिंह चुने गए। साल 1980 में यहां कांग्रेस के प्रेम साय सिंह विधायक चुने गए। साल 1985 में फिर से दोबारा प्रेम साय सिंह यहां से विधायक बने। लेकिन इसके बाद यहां विधायक कभी रिपीट नहीं हो सका। एक बार हराने के बाद ही जनता ने उन्हें दोबारा मौका दिया। साल 1990 में भाजपा के मुरारी लाल सिंह ने जीत दर्ज की। साल 1998 में कांग्रेस के प्रेम साय सिंह को जीत मिली। साल 2003 में भाजपा के राम सेवक पैकरा ने जीत हासिल की। वहीं, साल 2008 में कांग्रेस के प्रेम साय सिंह ने जीत दर्ज की। साल 2013 में भाजपा के राम सेवक पैकरा को जीत मिली। फिर साल 2018 में कांग्रेस के प्रेम साय सिंह ने यहां से चुनाव जीता।

सुधीर पांडे ने कहा आम तौर पर भाजपा हो या कांग्रेस सिटिंग विधायक को ही टिकट देती रही थी और परिणाम के रूप में विधायक हार जाते थे। लेकिन इस बार भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही यहां के समीकरण बदले हैं। दोनों ही दलों ने नए चेहरे को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने तो वर्तमान सरकार में शिक्षा और आदिवासी मंत्री रह चुके वरिष्ठ विधायक प्रेम साय सिंह का ही टिकट काट दिया है। हार जीत की परंपरा के अनुसार इस बार इस विधानसभा से कांग्रेस की हार और भाजपा की जीत संभावित है। लेकिन देखना होगा कि प्रत्याशी बदलने के फार्मूले के कारण क्षेत्र का पुराना रिकॉर्ड टूटेगा या बरकारार रहेगा।

प्रतापपुर विधानसभा सीट का ये रिकॉर्ड साल 1985 से लगातार जारी है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार यहां की जनता किस पार्टी पर भरोसा जताती है। क्या यहां से पुराना रिकॉर्ड टूटेगा? या फिर जनता दूसरे पार्टी को मौका देगी।

दिल्ली और पंजाब में भ्रष्ट सरकार का किया सफाया, आप भी दो मौका: केजरीवाल

मस्तूरी। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल में मस्तूरी में जनसभा को संबोधित किया।इस दौरान केजरीवाल ने जनता से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने की अपील की। केजरीवाल ने कहा कि देश में पहले दो ही राजनीतिक दलों के बीच जनता को चुनना होता था।लेकिन अब आपके सामने आम आदमी पार्टी का विकल्प है।हमने दो दो जगहों पर सरकार बनाई है।वहां की जनता को हम पर भरोसा है।दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को तीन बार बहुमत दिया।वो इसलिए क्योंकि हमारा काम बोलता है।

केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए लेकिन आजतक इन पार्टियों ने चुनाव में आकर नहीं कहा कि मैं अच्छे स्कूल बना दूंगा। अगर अच्छे स्कूल बन गए होते, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल गई होती तो आज देश गरीब नहीं होता।इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि दूसरे राजनीतिक दलों के लोग आपके पास वोट मांगने भी नहीं आते।हम आए हैं।इसलिए जो लोग आपसे वोट मांगने आए तो उसे जरुर दें।क्योंकि बच्चा भी मां से दूध तभी मांगता है जब उसे भूख लगती है।इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने चुनाव जीतने पर मुफ्त इलाज का वादा किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा दिल्ली और पंजाब की जनता ने झाड़ू उठाई और घपला करने वालों का सफाया कर दिया।आम आदमी पार्टी को मौका दिया।आम आदमी पार्टी ने सारे सरकारी स्कूलों को ऐसा बदला कि अब वहां गरीब का बच्चा पढ़कर डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आपको ऐसे डॉक्टर की जरुरत है जिसे बीमारी का पता हो।क्योंकि घुटनों का इलाज गले का डॉक्टर नहीं कर सकता।दूसरी पार्टी के लोगों को 100 के ऊपर की गिनती आती है।उनको गरीबों के बारे में नहीं पता।

कांग्रेस ने आदिवासियों को दिया उनका हक :भूपेश बघेल

रायपुर/कोण्डागांव। बस्तरवासी जिस काम को चाहते थे वह काम कांग्रेस की सरकार ने पिछले 5 सालों में करके दिखाया है, जल जंगल जमीन पर आदिवासियों को उनका अधिकार देने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। यह बात मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कोण्डागांव के माकड़ी में हुइ जनसभा में कही।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि विकास के दो पैमाने हैं जिसमें एक सड़क, पुल पुलिया, स्कूल, हॉस्पिटल का निर्माण है। दूसरा विकास का पैमाना व्यक्ति है। हमने व्यक्ति को केंद्र रखकर विकास किया है। बच्चे सुपोषित हों इसके लिए हमने मुख्यमंत्री सुपोषण योजना शुरू की, हमने अभियान चलाकर बस्तर को मलेरिया मुक्त किया, हमने बाजार में अस्पतालों को पहुंचा दिया। डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता था जिसे बढ़ाकर हम 10 लाख रुपये करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से हमने लोगों को इलाज में मदद की है।

रमन राज में बंद हो गए थे स?कूल

मुख?यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि बस्तर में रमन सिंह के राज में सैकड़ों स्कूल बंद हो गए थे, उन स्कूलों को शुरू करने का काम हमारी सरकार ने किया है। बस्तर में पहली बार स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोला गया। हमारे गरीब, मजदूर और किसान

के बच्चे भी अब अंग्रेजी स्कूलों में निःशुल्क पढ़ाई कर पा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनते ही सभी स्कूलों को स्वामी आत्मानंद स्कूलों में बदल जाएगा। हम वादा करते हैं कि केजी से पीजी तक की पढ़ाई में भी अब कोई शुल्क नहीं लगेगा।

कांग्रेस की गारंटी पर भरोसा

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि राहुल गांधी जी ने किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। हमने दो घंटे के भीतर 19 लाख किसानों का साढ़े 9 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ कर दिया। 25 सौ रुपये में धान खरीदने का वादा पूरा किया। अब तो किसान 2640 रुपये में धान बेच रहे हैं। हम इस बार फिर किसानों का कर्ज माफ करेंगे। हमारी इस घोषणा पर भाजपा के लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। जब वो लोग साढ़े 14 लाख करोड़ रुपये का कर्ज उद्योगपतियों का माफ कर सकते हैं, तो हम दोबारा किसानों का कर्ज क्यों नहीं माफ कर सकते।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि हर साल दो करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, काला धन लाकर सबसे खाते में 15 लाख रुपये डालेंगे, महंगाई कम करेंगे। मोदी ने अपना किया एक भी वादा पूरा नहीं किया। भाजपा के लोग ठगने और झूठ बोलने का काम करते हैं। आज सरसों का तेल, डीजल पेट्रोल के दाम सेंचुरी मार रहे हैं। मोदी जी झूठ बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ सारा धान वो खरीदते हैं। मोदी जी पहले यह बताएं कि अगर 2640 रुपये में छत्तीसगढ़ के किसान धान बेच रहे हैं तो जहां से वह सांसद हैं वाराणसी, वहां के किसान 1200 रुपये में धान बेचने को क्यों मजबूर हैं।

कांग्रेस पूरे करके रहेगी अपने वादे

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि महंगाई की वजह से लोग इस वक्त गैस के सिलेंडर भी नहीं भरवा पा रहे हैं, हम वादा करते हैं कि गैस रिफिलिंग पर 500 रुपये की सब्सिडी देंगे। 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी, साथ ही 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ का लाभ भी मिलेगा। साढ़े 17 लाख परिवारों को आवास देंगे। हम हर साल तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को 4000 रुपये देंगे। 700 रीपा खोला जाएगा। तिवरा को भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। जातिगत जनगणना समेत कांग्रेस की 17 गारंटियों को पूरा किया जाएगा।

भाजपा नहीं जांच एजेंसियां लड़ रही हैं चुनाव: भूपेश बघेल

महादेव बेटिंग ऐप मामले में भूपेश बघेल का नाम सामने आने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। बिना जांच मेरे ऊपर आरोप लगा दिए गए। भाजपा डरी हुई है इसलिए मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सीएम बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में चुनाव बीजेपी नहीं जांच एजेंसियां लड़ रही हैं।

खुद पर लगे आरोपों को लेकर सीएम बघेल ने कहा कि भाजपा के लोग सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकते इसलिए ईडी और आईटी के माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ईडी द्वारा भूपेश बघेल के खिलाफ किए गए दावे मुख्यमंत्री की छवि खराब करने के लिए भाजपा द्वारा रची गई एक साजिश है।महादेव सट्टेबाजी ऐप संबंधी आरोपों पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पीएम मोदी पूछ रहे हैं दुबई वालों से क्या संबंध है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि दुबई वालों से आपके क्या संबंध हैं? लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? यह गिरफ्तारी करना भारत सरकार का काम है। क्यों महादेव ऐप बंद नहीं हुआ था? ऐप बंद करना भारत सरकार का कर्तव्य है।सीएम बघेल ने कहा कि मैं पीएम से पूछना चाहता हूं कि आपकी डील क्या है? अगर डील नहीं हुई है तो ऐप बंद क्यों नहीं कर रहे हैं? बिना किसी जांच के आपने आरोप लगा दिया। ईडी और आईटी घूम रही है, होटल में पैसा कैसे पहुंचा?

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि जब भी चुनाव होते हैं तो भाजपा के लिए मुख्य हथियार ईडी और आईटी बन जाती है। हमने कर्नाटक चुनाव में देखा कि चुनाव के दौरान ही उन्होंने 100 से ज्यादा कांग्रेस उम्मीदवारों पर रेड की।

अमित जोगी ने ईडी ऑफिसर को सौंपा ज्ञापन

रायपुर। छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल चल रहा है। इस दौरान प्रदेश में ईडी का छापा मारने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इस बीच जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी आज शनिवार को ईडी कार्यालय पहुंचे। वे पचपेड़ी नाका कार्यालय पहुंचकर ईडी के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है।

उनके साथ कार्यकर्ता पोस्टर लेकर खड़े नजर आए।

अमित जोगी ने ज्ञापन में कहा कि प्रदेश में लगातार ईडी छापेमारी कर रही है। यह सिलसिला लगातार जारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि महादेव सट्टा घोटाले के मुख्य अभियुक्तों ने बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपए छत्तीसगढ़ के सीएम और उनके सहयोगी को दिए गए हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।

अमित जोगी ने कहा कि जिस राज्य में 45त्न आबादी गरीबी में जीने के लिए विवश हैं और 20 लाख से ज्यादा परिवार आवासहीन जीवन यापन कर रहे हैं। उसे राज्य के लोगों के करोड़ों रुपए महादेव एप को सत्ता का माध्यम बनाकर लूटे गए हैं और लूटने वाले कोई और नहीं बल्कि सत्ताधारी दल की सरकार के मुख्य और उनके सहयोगी हैं।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के सवा तीन करोड़ लोगों की ओर से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे यह निवेदन करती है कि परिवर्तन निदेशालय महादेव एप सट्टे छापेमारी में जब्त करोड़ों रुपए छत्तीसगढ़ सरकार को दिए जाए ताकि इस माध्यम से यह पैसा छत्तीसगढ़ के गरीबों के बैंक खाते में जमा हो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और कथित रूप से महादेव ऐप से काली कमाई के 508 करोड रुपए भी तत्काल उनकी संपत्ति कुर्क कर वसूले जाए। उन्होंने कहा कि जब्त पैसों को छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के बैंक खाता में डाले जाए।

संक्षिप्त समाचार

मतदान के दिन सभी निजी और सरकारी संस्थानों में रहेगी छुट्टी

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा की चुनाव दो चरणों में होनी है। पहला चरण 7 नवंबर को और दूसरा चरण 17 को होगा। दो मतदान दिवस के लिए सभी शासकीय और प्राइवेट संस्थानों में छुट्टी की घोषणा की गई है। इसके साथ ही वे कार्यालय और संस्थान भी शामिल हैं, जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत शामिल हैं। निजी संस्थानों, औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अधिकारी और कर्मचारियों को सवैतनिक छुट्टी रहेगी। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार श्रम विभाग ने विधानसभा चुनाव के लिए औद्योगिक, व्यावसायिक और संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मतदान दिवस पर छुट्टी दिया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 151 की धारा 135 के तहत प्रत्येक चुनाव क्षेत्र के कर्मचारियों को छुट्टी देने की बात कही है। इसके साथ अन्य राज्यों में भी इसी तरह सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। सवैतनिक अवकाश नहीं देने पर नियोक्ता पर दंडनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। आयोग के अनुसार वे कर्मचारी भी अवकाश के पात्र होंगे, जिनका नाम अन्य चुनाव क्षेत्र में दर्ज है। सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं उन कारखानों में पहले और दूसरे पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन दो-दो घंटे का छुट्टी दिया जाए। बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाए।

डाक मतपत्र से मतदान 05 नवंबर तक

कांकेर। विधानसभा निर्वाचन में पुलिस विभाग एवं अन्य विभाग के जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा अन्य जिले के कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान नहीं कर पाए हैं। ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी 05 नवम्बर को डाक मतपत्र सुविधा केन्द्र संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन, तृतीय तल, कक्ष क्रमांक-15 के प्रशिक्षण हॉल में प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक उपस्थित होकर मतदान कर सकेंगे। इस संबंध में बताया गया है कि इसके अलावा 06 नवम्बर को मतदान सामग्री वितरण केन्द्र शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज नाथियानवागांव में प्रातः 08 बजे से मतदान दल की रवानगी तक डाक मतपत्र से मतदान किया जा सकेगा।

भानुप्रतापपुर में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस पर निशाना

रामभक्तों पर लाठीचार्ज करवाती है कांग्रेस

कांकेर। भानुप्रतापपुर पहुंचे बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ में है और रामजी का घर अयोध्या में है। ननिहाल से कोई कमी न रह जाए, इस बात का ख्याल आपको रखना है, तभी रामराज्य आएगा। योगी ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का सरकार के संरक्षण में खेल चल रहा है। योगी ने कहा कि लव जिहाद करने वाले लोगों पर सरकार कार्रवाई नहीं करती है। कांग्रेस को डर रहता है कि अगर खास वर्ग के लोगों पर कार्रवाई करेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। उस खास वर्ग को खुश रखने के लिए ये सरकार लव जिहाद को बढ़ावा दे रही है। राम भक्तों का अपमान करने का काम यह सरकार कर रही है।

योगी ने बघेल सरकार पर आरोप लगाया कि रामनवमी के जुलूस पर ये सरकार लाठीचार्ज करवाती है और पत्थर फेंकने वालों के साथ जाकर खड़ी हो जाती है। आदित्यनाथ यहीं नहीं रुके उन्होने कहा कि इनके एक बिहार के पार्टनर ने चारा घोटाला किया था उनसे प्रेरणा लेकर यहां की सरकार ने गोबर घोटाला कर दिया। ऐसे भ्रष्टाचारियों को हमें खत्म करना है। कर्ज माफी की बात कही थी वो भी पूरा नही किया। केंद्र की योजनाओं की तारीफ करते हुए

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आयुष्मान कार्ड जैसी योजना दी। एक रुपए किलो चावल देने की योजना रमन सिंह ने शुरु किया जिसे दूसरे राज्यों ने भी अपनाया। योगी ने कहा कि छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का गढ़ नहीं बनने देना है, विकास का गढ़ बनाना है। कांग्रेस ने आतंकवाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार को जन्म दिया है। हमने ही छत्तीसगढ़ को बनाया और हम ही इसे संवारेंगे। बीजेपी हर हाल में ये चाहती है कि बस्तर से बीजेपी चुनाव में बेहतर शुरुआत करे ताकि उसका फायदा दूसरे चरण के मतदान जो कि 17 नवंबर को होना है उसमें मिले। इधर योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग सभाओं में पहुंच रहे हैं, जिससे बीजेपी के कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं।

जेसीसीजे कितना पहुंचा सकती है नुकसान, क्या 2003 का इतिहास दोहराएगा छत्तीसगढ़?

बिलासपुर। 2003 में जोगी सरकार को हटाने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बैनर पर पूरे 90 सीटों पर चुनाव लड़वाया था। उसी तरह इस बार भी जेसीसीजे ने पूरे 90 विधानसभा से प्रत्याशी खड़ा किया है। ऐसा माना जा रहा है कि इससे कहीं ना कहीं नुकसान कांग्रेस को होगा। 2003 में पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बैनर तले पूरे 90 विधानसभा में अपने प्रत्याशी खड़े किए थे।

2003 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कोई खासी सफलता हासिल नहीं हुई थी। मात्र एक सीट चंद्रपुर से नोबेल वर्मा ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जीते थे। लेकिन कांग्रेस की अजीत जोगी की सरकार को उखाड़ फेंकने में एनसीपी की अहम भूमिका थी। यही वजह है कि इस बार भी आम जनता

जेसीसीजे को लेकर वही सोच रखती है। जनता का मानना है कि यदि 2003 के चुनाव की पुनरावृत्ति होगी तो इस बार भी कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, लेकिन इस मामले में राजनीती जानकार कुछ अलग ही कहते हैं।

राजनीती के जानकार निर्मल माणिक का कहना है कि 2003 में एनसीपी ने एक सीट जीती थी। लेकिन जब पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने जेसीसीजे का गठन किया तो उन्होंने बसपा से गठबंधन कर चुनाव लड़ा। जिसका नतीजा ये रहा कि बसपा के दो विधायक बने और उनकी पार्टी ने प्रदेश में पांच सीटों पर कब्जा कर लिया। इस बार की स्थिति कुछ अलग है। इस बार ना तो अजीत जोगी रहे और ना ही जेसीसीजे ने बसपा से गठबंधन किया है। इसके साथ ही न तो देवव्रत सिंह रहे और ना लोरमी विधायक धर्मजीत उनकी पार्टी में है। धर्मजीत सिंह भाजपा में, बलौदा बाजार के विधायक प्रमोद सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए है। निर्मल माणिक की माने तो जेसीसीजे के पास केवल एक ही विधायक रह गई है।वो हैं रेणु जोगी। बाकी लोग पार्टी में नहीं है। अभी जिन लोगों को चुनाव में टिकट दिया गया है। उनमें ज्यादातर कांग्रेस से नाराज लोग ही चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी ने जब उन्हें टिकट नहीं दिया तो वह बगावत कर चुनाव लड़ रहे हैं। उनका उद्देश्य केवल यह है कि उन्हें कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना है। जीत और हार से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, वैसे भी प्रदेश में बहुत कम ही लोग है जो दलबदलुओ को पसंद करते हैं।

भाजपा की घोषणा पत्र पर सुशील आनंद ने कसा तंज

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने आज शुक्रवार को घोषणा पत्र जारी कर दी है। इस पर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाते हुए कहा कि घोषणा पत्र भाजपा कांग्रेस की नकल करने की कोशिश की है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। आनंद शुक्ला ने धान खरीदी को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है।

सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि यह भूपेश बघेल की उपलब्धि है कि धान पर बोनस का विरोध करने वाले धान की कीमत 3100 करने की बात कर रहे है, जो लोग 2100 बोलकर नहीं दिये, 300 बोनस नहीं दिये, जो लोग 15 क्विंटल नहीं खरीदने का निर्णय लिये थे वे अब 21 क्विंटल खरीदने की बात कर रहे। यह भूपेश बघेल की उपलब्धि है। उन्होंने भाजपा को घेरते हुए कहा कि बीजेपी घोषणा तो कर रहे, लेकिन इस पर जनता भरोसा नहीं करेगी। मोदी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने कह कि जो मोदी 15 लाख देने का वायदा भूल गए। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा भूल गए। 100 दिन में महंगाई कम करने का वायदा भूल गए। किसानों की आय दुगुनी करने के वायदे तो आज तक पूरे नहीं हुए उनकी क्या गारंटी है। दिग्विजय सिंह की सरकार ने बनाया था। भूपेश सरकार संवार रही। जो हम 5 साल से कर रहे है, भाजपा उसको करना चाह रही है। वह हमारे पिच पर खेलने को मजबूर हुई।

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा वोट लेने के लिए फिर किसानों को ठगना चाहती। धान की कीमत 3 हजार 100 रुपए करने की घोषणा किया है, तो बताए क्या केन्द्र धान का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 3 हजार रुपए करेगी। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि क्योंकि मोदी तो धान की कीमत समर्थन मूल्य से 1 रुपए भी ज्यादा देने के विरोधी हैं। आनंद शुक्ला ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के 2500 रुपए देने का विरोध किया था, धमकी दी थी। ऐसे में भाजपा मोदी सरकार के विरोध में जा कर 3 हजार रुपए कैसे देगी यह स्पष्ट करें। 2400 देने का वायदा, तो 2013 में भी किया था नहीं दिया। दूसरा बड़ा झूठ 21 क्विंटल धान खरीदने का वायदा भी है। उन्होंने कहा कि पहले 2013 में भी यही वायदा किया था, लेकिन लिमिट घटाकर 15 से 10 कर दिया कैसे भरोसा करें कि आपने वायदे पर कायम रहेंगे? शुक्ला भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि किसानों के कर्जामाफी पर कुछ नहीं बोल रहे।

बीजेपी के घोषणा पत्र जारी होने के बाद सुशील ने तंज कास्ट हुए कहा कि वायदा तो कर लोगे, भरोसा कौन करेगा, क्यों करेगा? 500 में सिलेंडर देने की बात भी धोखा इनकी केन्द्र सरकार सिलेंडर के दाम 400 से बढ़ाकर 1000 के उपर किया। अब ये 500 में सिलेंडर देने की बात कर रहे। भाजपा सिर्फ बीपलएल को गैस सिलेंडर देगी। कांग्रेस हर वर्ग को 500 रुपए सब्सिडी दे रही मतलब सिर्फ 450 में सिलेंडर मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने 17.5 लाख आवास देने का वायदा किया, तो नकल करके 18 लाख देने की बात कर रहे। 15 साल में सरकारी नौकरी के द्वार बंद कर दिया था, अब नौकरी देने का झूठा वायदा कर रहे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 10 लाख तक ईलाज का वायदा किया है उसको भी नकल कर रहे हैं। राज्य में भूपेश सरकार 20 क्विंटल धान की खरीदी शुरू कर चुकी है। उसकी नकल में 21 क्विंटल की बात भाजपा कर रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भूपेश है तो भरोसा है, भरोसा बरकरार फिर से कांग्रेस सरकार। नारा भी हमारा चुराते है घोषणाएं भी हमारे चुराते है। घोषणा तो कर लेंगे लेकिन भरोसा कहां से लाओगे।

पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले फँस गये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

नीरज कुमार दुबे

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर सट्टेबाजों से कथित रूप से 508 करोड़ रुपए लिए जाने का आरोप लगने से राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान से ठीक पहले किये गये इस दावे से जहां कांग्रेस सकते में आ गयी है वहीं भाजपा ने अपना हमलावर रुख और तेज कर दिया है। हम आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दावा किया है कि फॉरेंसिक विश्लेषण और पैसे का लेन-देन करने वाले एक व्यक्ति के बयान में चौंकाने वाले आरोप सामने आए हैं कि महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रवर्तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुके हैं। ईडी ने कहा कि यह जांच का विषय है।

इसके बाद शनिवार सुबह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को घेरते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि भूपेश बघेल के खिलाफ कुछ चौंका देने वाले तथ्य देश के सामने प्रस्तुत हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं आज कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूं कि क्या ये सत्य है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेताओं को शुभम सोनी के माध्यम से असीम दास पैसा पहुंचाते थे? स्मृति ईरानी ने पूछा क्या ये सत्य है कि शुभम सोनी के एक वॉइस मैसेज के माध्यम से असीम दास को ये आदेश दिया गया कि वो रायपुर जाएं और भूपेश बघेल को चुनाव के खर्चे के लिए पैसा दें?

दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी पर राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले उनकी छवि धूमिल करने का ''दुर्भावनापूर्ण प्रयास'' करने का आरोप लगाया है। बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर राज्य में कांग्रेस से मुकाबला करने में विफल रहने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसियों का सहारा लेने का आरोप लगाया। बघेल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी, आईटी (आयकर विभाग), डीआरआई (राजस्व खुफिया निदेशालय) और सीबीआई जैसी एजेंसियों के सहारे छत्तीसगढ़ का चुनाव लड़ना चाहती है। चुनाव के ठीक पहले ईडी ने मेरी छवि धूमिल करने का सबसे कुत्सित प्रयास किया है। यह कांग्रेस की लोकप्रिय सरकार को बदनाम करने का राजनीतिक प्रयास है, जो ईडी के माध्यम से किया जा रहा है।%

बघेल ने लिखा, महादेव ऐप की कथित जांच के नाम पर ईडी ने पहले मेरे करीबी लोगों को बदनाम करने के लिए उनके घर छापे मारे और अब एक अनजान से व्यक्ति के बयान को आधार बनाकर मुझ पर 508 करोड़ रुपये लेने का आरोप लगा दिया है। ईडी की चालाकी देखिए कि उस व्यक्ति का बयान ज़ाहिर करने के बाद एक छोटे से वाक्य में लिख दिया है कि बयान जांच का विषय है। अगर जांच नहीं हुई है तो एक व्यक्ति के बयान पर प्रेस विज्ञप्ति जारी करना न केवल ईडी की नीयत को बताता है बल्कि इसके पीछे केंद्र सरकार की बदनीयती को भी ज़ाहिर करता है। मुख्यमंत्री ने पोस्ट में लिखा, इस समय राज्य में चुनाव हो रहे हैं। सब कुछ निर्वाचन आयोग के हाथों में है। पुलिस के अलावा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवान जांच कर रहे हैं। ऐसे में

सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी रकम लेकर लोग किस तरह से छत्तीसगढ़ पहुंच पा रहे हैं? कहीं इसमें भी तो केंद्रीय एजेंसियों की सांठगांठ नहीं चल रही है? कहीं ये रकम उन संदूकों में तो भरकर नहीं लाई गई है जो ईडी के अफसरों और सुरक्षा एजेंसियों के साथ विशेष विमान से पहुंची है?

उन्होंने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, दोनों मिलकर भी कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं तो वे जांच एजेंसियों के सहारे चुनाव लड़ना चाहते हैं। बघेल ने पोस्ट में लिखा है, ईडी के खिलाफ़ मैंने खुले बयान दिए हैं और जनता को बताता रहा हूं कि ईडी किस तरह से काम करती है। वह पहले लोगों के नाम तय करती है, फिर लोगों को गिरफ्तार करके धमकाती, डराती है और नाम लेने के लिए बाध्य करती है। इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। मारना, डराना धमकाना तो सामान्य बात है। उन्होंने लिखा, कांग्रेस तैयार है। कांग्रेस का एक-एक कार्यकर्ता तैयार है। ईडी, आईटी जैसी एजेंसियों के मुकाबले के लिए छत्तीसगढ़ की जनता हमारे साथ है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। राज्य के 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए सात और 17 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा।

जहां तक ईडी के आरोप की बात है तो आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि फॉरेंसिक विश्लेषण और पैसे का लेन-देन करने वाले एक व्यक्ति के बयान में चौंकाने वाले आरोप सामने आए हैं कि महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रवर्तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुके हैं। हम आपको बता दें कि एजेंसी चुनाव वाले राज्य छत्तीसगढ़ में पैसे का लेन-देन करने वाले असीम दास (38) के पास से 5.39 करोड़ रुपये बरामद करने के बाद उसे रायपुर से गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी ने कहा है कि ऐप के प्रवर्तकों ने विशेष रूप से, सत्तारुढ़ कांग्रेस पार्टी के लिए चुनावी खर्चों के लिए बड़ी मात्रा में नकदी पहुंचाने को लेकर असीम दास को कथित तौर पर यूएई से भेजा था।

एजेंसी ने एक बयान में आरोप लगाया, असीम दास ने स्वीकार किया है कि महादेव ऐप के प्रवर्तकों ने जब्त की गई धनराशि छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव में होने वाले खर्चों के लिए एक नेता बघेल तक पहुंचाने की व्यवस्था की थी। एजेंसी ने कहा, असीम दास से पूछताछ, उसके पास से बरामद फोन की फोरेंसिक जांच और शुभम सोनी (महादेव नेटवर्क के उच्च पदस्थ आरोपियों में से एक) द्वारा भेजे गए ईमेल की पड़ताल से कई चौंकाने वाले आरोप सामने आए हैं। पता चला है कि महादेव ऐप के प्रमोटर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अतीत में नियमित तौर पर भुगतान करते रहे हैं और अब तक लगभग 508 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

असीम दास और पुलिस कांस्टेबल भीम यादव (41) की हिरासत की मांग करते हुए अदालत में दायर अपने रिमांड आवेदन में, ईडी ने कहा कि भूपेश बघेल पर लगे आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करने की आवश्यकता है। हिरासत अनुरोध के साथ असीम दास के आईफोन से बरामद एक ऑडियो क्लिप की प्रति भी साझा की गई, जिसमें शुभम सोनी को विशेष रूप से असीम दास को छत्तीसगढ़ के आगामी चुनावों में खर्च के लिए बघेल को धन की आपूर्ति करने के लिए तत्काल रायपुर जाने के लिए कहते हुए सुना जा सकता है। एजेंसी ने पहले कहा था कि ऐप से अर्जित कथित अवैध धन राज्य में नेताओं और नौकरशाहों को रिश्वत के रूप में दिया गया था। हम आपको बता दें कि ईडी ने कई मशहूर हस्तियों और बॉलीवुड कलाकारों को बुलाकर ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म से उनके संबंधों और इसके भुगतान के तरीके के बारे में पूछा था। ईडी ने कहा कि उसे खुफिया जानकारी मिली थी कि छत्तीसगढ़ में सात और 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए महादेव ऐप के प्रवर्तकों की तरफ से बड़ी मात्रा में धन ले जाया जा रहा है, इसके बाद उसने बृहस्पतिवार को दास को पकड़ा था। ईडी ने कहा कि यह धन राज्य के दुर्ग जिले के भिलाई स्थित होटल 'ट्राइटन' में खड़े एक वाहन से जब्त किया गया था।

उत्तर भारत में कर्नाटक की रणनीति का असर

अजय सेतिया

चुनाव वाले तीनों हिन्दी भाषी राज्यों में तस्वीर अब थोड़ी थोड़ी साफ़ होने लगी है। भाजपा और कांग्रेस के अधिकांश उम्मीदवारों का एलान हो चुका है। उम्मीदवारों की सूची देखकर एक बात साफ़ हो गई है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों की रणनीति कर्नाटक के नतीजे से प्रभावित है। राजस्थान और मध्यप्रदेश में कांग्रेस का फोकस मुस्लिम वोटरों को एकजुट रखने का है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का बड़ा कारण मुस्लिम वोटों का एकतरफा कांग्रेस की ओर जाना ही था। अगर जेडीएस और कांग्रेस में मुस्लिम वोटों का बंटवारा होता, तो ऐसे नतीजे नहीं आते। इन नतीजों से सबक सीख कर ही एचडी देवेगौडा ने भाजपा के साथ गठबंधन का फैसला किया। अपनी पार्टी में विभाजन की कीमत पर उन्होंने ऐसा किया। कर्नाटक में भी जेडीएस टूट गई और केरल यूनिट तो अलग ही हो गया। जब जनता दल के कई टुकड़े हुए थे, तो देवेगौडा ने अपनी पार्टी के नाम के साथ ही सेक्यूलर जोड़ा था। तब जो पार्टी जेडीयू भाजपा के साथ गई थी, वह तो सेक्यूलर हो कर कांग्रेस के साथ चली गई, और सेक्यूलर पार्टी भाजपा के साथ चली गई। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का दूसरा बड़ा कारण दलित वोट बैंक था, जो एकतरफा कांग्रेस के साथ चला गया था। वह कर्नाटक के दलित समुदाय से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे की वजह से हुआ था, जिन्हें कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष बनाया था। लेकिन उत्तर भारत में भाजपा को दलित वोटों के खिसकने का खतरा नहीं है। उत्तर भारत की राजनीति कभी भी दक्षिण से प्रभावित नहीं होती, और दक्षिण की राजनीति कभी भी उत्तर से प्रभावित नहीं होती। दक्षिण भारत में दलितों का अच्छा खासा वोट बैंक होने के बावजूद कांशीराम और मायावती कभी भी दक्षिण में पाँव नहीं जमा सके। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में जहां दलित समुदाय आधारित आरपीआई का अच्छा खासा प्रभाव है, कांशीराम और मायावती प्रभाव नहीं जमा सके। अलबत्ता रामजन्मभूमि आन्दोलन के बाद उत्तर भारत का दलित समुदाय भाजपा से जुड़ा है। इसलिए उत्तर प्रदेश में भी मायावती का सफाया हो गया। भाजपा को उत्तर भारत में दलित वोटों में विभाजन का खतरा नहीं है। इसमें छत्तीसगढ़ जैसे कुछ राज्य अपवाद हैं, जहां दलित और आदिवासी वोटर भाजपा से सत्ता में भागेदारी नहीं मिलने से नाराज होकर कांग्रेस के साथ खड़ा दिख रहा है। भाजपा को सबसे ज्यादा खतरा मोदी की सबका विकास वाली छवि से है, जिस कारण हिन्दुओं का एक बड़ा वोट बैंक भाजपा से खफा है। नूपुर शर्मा के मामले में कट्टरपंथी मुस्लिमों के सामने भाजपा के घुटने टेकने से भी भाजपा का वोटर खफा है। इसलिए भाजपा के सामने बड़ी चुनौती अपने ही वोट बैंक को संभाल कर रखने की है। हिन्दू वोट बैंक को संभाल कर रखने के लिए भाजपा ने कट्टरवादी हिन्दू नेता के तौर पर उभरे योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्व सरमा को तीनों राज्यों में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की रणनीति बनाई है। मौके को ताड़ कर कमलनाथ ने मध्यप्रदेश में खुद की हिन्दूवादी छवि बनानी शुरू की। तो शुरुआती विरोध के बाद दिग्विजय सिंह ने भी रामजन्मभूमि मन्दिर के लिए एक लाख ग्यारह हजार रूपए भेजने की बात कही है। भाजपा और संघ के कई बड़े नेता भी भाजपा से नाराज हो कर कांग्रेस में चले गए हैं। मध्यप्रदेश में कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व वाले कार्ड ने मुकाबले को कड़ा बना दिया है। जैसा कि कमलनाथ ने पिछली बार कहा था कि मुसलमानों ने 90 प्रतिशत वोटिंग की तो कांग्रेस ही जीतेगी, वही फार्मूला इसबार भी है। अगर कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की लाईन अपनाती है तो मुसलमानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मध्यप्रदेश में कांग्रेस मस्जिदों का जमकर इस्तेमाल कर रही है। भाजपा ने इसे ध्रुवीकरण के मौके के तौर पर लिया है, और चुनाव आयोग को लिखित में शिकायत भेजी है। जब इस तरह की खबर बाहर आती है, तो प्रतिक्रिया में ध्रुवीकरण अपने आप हो जाता है। ठीक चुनावों के समय रामजन्मभूमि मन्दिर के उद्घाटन की खबर ने भी भाजपा के वोट बैंक की नाराजगी दूर करने का काम किया है।

विपक्षी एकता के सारे दावे हवा हवाई

योगेंद्र योगी

देश के पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव से विपक्षी एकता गठबंधन इंडिया बनने से पहले ही बिखरने के कगार पर आ गया है। लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन के प्रमुख दल सबसे प्रमुख राज्यों में आपस में ही संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस, जनता दल युनाइटेड, समाजवादी पार्टी और आप में सीट बंटवारे के लिए तनाव बढ़ रहा है। इन दलों के नेता और कार्यकर्ता भी आपस में दंगल कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में गैरभाजपा दलों की फूट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में गठबंधन का अंजाम क्या होगा। सपा के नेता ने अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया है और कांग्रेस के कार्यकर्ता ने अजय राय को यूपी का अगला सीएम बताया है। इससे इंडिया गठबंधन का तालमेल खराब हो रहा है।

विपक्ष के 26 दलों का जब गठबंधन हुआ तब कहा गया वे सारे देश में भाजपा के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन गठबंधन के सबसे बड़े दल कांग्रेस ने साफ कहा है कि इंडिया का गठन 2024 लोकसभा चुनावों के लिए हुआ न कि विधानसभा चुनाव के लिए। कांग्रेस ने इसी रणनीति के तहत पांच राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में अपने किसी सहयोगी दल को तवज्जो नहीं दी। मिजोरम को छोड़कर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की भाजपा से सीधी लड़ाई है। वहीं, तेलंगाना में उसका मुकाबला के. चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति से है। मध्य प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और सपा में शुरू हुआ तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया। दोनों तरफ से ये दावा किया गया है कि बीजेपी को हराने के लिए चुनावी तालमेल जरूरी था, पर ऐसा नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस पर धोखेबाजी का आरोप लगा रही है। यही बात कांग्रेस पार्टी के नेता समाजवादी पार्टी के लिए कह रहे हैं।

कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात पक्की न हो पाने के बाद मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के 45 उम्मीदवार उतार चुके

हैं और इसी तरह नीतीश कुमार भी अब तक जेडीयू के 5 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुके हैं। जेडीयू की तरफ से दर्जन भर उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाले हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने अब तक किसी अन्य दल से गठबंधन नहीं किया है। साथ ही प्रदेश की सभी 200 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। पार्टी की ओर से जारी अब तक तीन लिस्ट में 49 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है।

विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच विपक्षी दलों में अभी से घमासान मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के बाद सपा दूसरे नंबर की पार्टी है लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की स्थिति ज्यादा मजबूत है। ऐसे में राष्ट्रीय पार्टी सपा से किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के मुख्य मुकाबले में कांग्रेस है और इसलिए सपा को सीटें देने से पार्टी ने गुरेज किया था। इसे लेकर अखिलेश यादव ने आपत्ति जताई थी और सवाल किया था कि क्या यह गठबंधन राज्य स्तर पर है या नहीं? तब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सपा की स्थिति की याद दिलाते हुए उसे कांग्रेस को सहयोग देने की अपील की थी। ऐसे में माना जा रहा है कि यही तर्क यूपी में सीट बंटवारे के दौरान अखिलेश भी कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मैदान में आमने सामने तो बीजेपी और कांग्रेस हैं, लेकिन निशाने पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव आ रहे हैं और सूबे के सियासत की आंच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंच रही है। असल में ये सारी बातें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच चुनावी गठबंधन को लेकर चल रही हैं। लंबे समय से अखिलेश यादव को लेकर राहुल गांधी का जो रुख सामने आया है, उसका सीधा असर इंडिया गठबंधन पर पड़ना निश्चित है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में विपक्ष एकजुट नहीं हो पाता तो देश के बाकी हिस्सों में साथ होकर भी कोई फायदा नहीं होने वाला है।

क्षेत्रीय दल कांग्रेस के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, ये तो राहुल गांधी ने कांग्रेस के उदयपुर मंथन शिविर में उनकी विचारधारा पर टिप्पणी करके जता दिया था। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने साफ तौर पर यही समझाने की कोशिश की थी कि क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करना ही होगा। राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर कर्नाटक से लेकर बिहार जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई थी। अगर दिल्ली अर्थात प्रधानमंत्री पद का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता हुआ माना जाता है, तो ये भी मान कर चलना चाहिये कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के मामले में भी यही बात लागू होती है। ऐसे में समाजवादी पार्टी को हल्के में लेना राहुल गांधी के लिए बहुत भारी पड़ सकता है।

वर्ष 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन का स्लोगन था यूपी को ये साथ पसंद है। ये साथ राहुल गांधी और अखिलेश यादव का ही था। दोनों नेता तब साथ-साथ चुनावी रैलियां और रोड शो भी करते रहे। प्रियंका गांधी भी यूपी के लड़कों के साथ को काफी उत्साह भरी नजर से देख रही थीं। माना जाता है कि तब प्रियंका गांधी वाड्रा ने ही दोनों दलों के बीच चुनावी गठबंधन कराया था और ऐसा करने के लिए उनको डिंपल यादव की भी थोड़ी मदद लेनी पड़ी थी। फिर डिंपल यादव ने अखिलेश यादव को और प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी को गठंबधन के लिए मना लिया था। कांग्रेस ने मोलभाव करके काफी सीटें ले लीं, लेकिन नतीजे आये तो बुरी तरह लुढ़क गई। अखिलेश यादव सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहे थे और उनको बड़ी उम्मीद थी कि उनकी साइकिल पर कांग्रेस का हाथ लग जाये तो वो आसानी से रफ्तार पकड़ लेगी। चुनाव बाद गठबंधन टूट गया। गठबंधन टूट जाने के कई कारण माने जाते हैं, जिनमें एक कारण ये भी कहा जाता है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव को भाव नहीं दे रहे थे।

वर्ष 2019 के आम चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने मायावती के साथ गठबंधन किया और गठबंधन से कांग्रेस को पूरी तरह दूर रखा गया। बस रायबरेली और अमेठी सीट पर कांग्रेस को बख्श दिया गया, फिर भी राहुल गांधी की हार के साथ कांग्रेस को अमेठी सीट गंवानी पड़ी थी। इंडिया गठबंधन के विपक्षी दलों की अब तक तीन बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में सिर्फ भाजपा के खिलाफ हुंकार भरने से ज्यादा प्रगति नहीं हो सकी। भाजपा इंडिया के विपक्षी दलों के खिलाफ किसी तरह का मुद्दा हाथ से नहीं जाने दे रही है। मुद्दा चाहे भ्रष्टाचार का हो या फिर दूसरे क्षेत्रीय-राष्ट्रीय चुनावी महत्व का। विधानसभा चुनाव से विपक्षी दलों की सूरत नजर आने लगी है। इस बिगड़ी हुई सूरत को संवार भाजपा को उसी हालत में चुनौती दी जा सकती है, जब क्षेत्रीय दल अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर एकता की कवायद करेंगे।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

महोपनिषद् (भाग-33)

गतांक से आगे...

हे द्विज। यदि आपके हृदय में इन्द्रियजन्य विषय हलचल पैदा नहीं करते, तो आप ज्ञातव्य पदार्थ का ज्ञान प्राप्त कर संसार रूपी समुद्र से पार हो गये। विशिष्ट ज्ञानयुक्त होकर वासनारूपी फूलों की सुगन्ध से अपनी चित्तवृत्ति को जल्दी ही दूर कर लिया जाए, तो महान् पद की प्राप्ति हो सकती है।

वासनारूपी जल से युक्त इस संसार सागर में जो सद्ज्ञान रूपी नौका पर आरूढ़ हैं, वे ज्ञानीजन इससे पार हो गये। सांसारिक प्रपञ्च के जानकार पुरुष सांसारिक व्यवहार का न तो परित्याग करते हैं और न ही उसकी कामना करते हैं; अपितु वे उनके प्रति अनासक्ति का ही व्यवहार करते हैं, ज्ञानियों ने संकल्प का अंकुरित होना ही अनन्त आत्मतत्त्वरूप चेतन का विषयासक्त होना माना है। वही संकल्प अल्पमात्र स्थान प्राप्त करके धीरे-धीरे सघन होते हैं; तत्पश्चात् वे मेघ की तरह सुदृढ़ होकर चित्ताकाश को ढककर जड़त्व भाव का संचार करते हैं।

बीज के अंकुरावस्था को प्राप्त करने के समान ही चेतन विषयों को स्वयं से अलग सा मानते हुए वह संकल्पावस्था को प्राप्त होता है। संकल्प से उसकी क्रिया अपने आप ही प्रकट होती है और स्वयं ही शीघ्रातिशीघ्र वृद्धि को प्राप्त होती है। लेकिन वह दु:ख का ही कारण बनती है, सुख देने वाली नहीं होती। चित्त में उत्पन्न होने वाली संकल्प क्रिया को रोके। उसमें पदार्थ भावना न करे, जिसने संकल्प को विनष्ट करने का निश्चय किया है, उसे पुन: उसका अनुगमन करना उचित नहीं। [चेतन के ऊपर चढ़े विकार की तुलना धान के छिलके से की गई है। विकार हटाये बिना चावल सेवन करने योग्य नहीं होता और पुन: फलित होने के लिए छिलका विकार आवश्यक है। छिलका विकार हटते ही वह ज्ञानी के लिए सेव्य है तथा पुनर्जन्म के चक्र की संभावना भी समाप्त हो जाती है।] हे निष्पाप ! अन्तरंग की आस्था एवं भावनायुक्त भावों की सम्पदा का परित्याग करके आप अपने वास्तविक रूप में संसार में सुखपूर्वक विचरण करें। सभी जगह स्वयं को अकर्तृता मानें, इस सुदृढ भावना से परम अमृत नाम की समता (एकरसता) ही अवशिष्ट रहती है।

दु:ख और उल्लास - विलास-ये मनुष्य द्वारा स्वत: उत्पादित हैं। अपने संकल्प के क्षय होने पर समता भाव ही अवशेष रहता है। सभी पदार्थों में समता की वास्तविक स्थिति को चित्त में निष्ठापूर्वक धारण कर लेने पर आवागमन का चक्र समाप्त हो जाता है। हेमुने! सभी कर्तृत्व्य तथा अकर्तृत्व्य का त्यागकर, मन का पान कर आप अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिर हों। बाद में समाधिस्थ होकर जिससे आप त्याग किया करते हैं, उसे भी छोड़ दें। चेतन ने ही मानसिक संकल्प का आकार धारण कर रखा है, वही प्रकाश और अंधकार का रूप धारण किये हुए है। अत: प्राणस्पन्दन के साथ-साथ वासना का सम्पूर्ण परित्याग करके आकाश की तरह निर्मल और शान्त मन वाले बनें। **क्रमश: ...**

चितरंजन दास

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चितरंजन दास का नाम कई योगदानों के कारण लिया जाता है। देशबंधु के नाम से मशहूर सीआर दास स्वतंत्रता सेनानी, सुप्रसिद्ध वकील, पत्रकार, कवि और राजनीतिज्ञ थे जिन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी एक स्वतंत्र छाप छोड़ी थी और कभी भी अपने सिद्धांतों और विचारों से समझौता नहीं किया और यहां तक कि उन्होंने गांधी जी का भी विरोध किया और अंजाम की परवाह नहीं की लेकिन गांधी जी के आंदोलन के लिए सपत्नीक जेल भी जाने से नहीं हिचकिचाए। उन्हें देशबंधु की उपाधि यूं ही नहीं दी गई थी।

चितरंजन दास का जन्म 5 नवंबर 1870 को कोलकाता में वैद्य परिवार में हुआ था। वे कोलकाता उच्च न्यायलय के जाने माने वकील भुबन मोहनदास के पुत्र थे। उन्होंने कोलकत्ता के प्रेसिडेसी कॉलेज से स्नातक की पढ़ी की और फिर आईसीएस की परीक्षा भी दी जिसमें वे पास नहीं हो सके। इसके बाद उनहोने लंदन में वकालत की पढ़ाई की और फिर कोलकाता उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। वह भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की अवधि के दौरान बंगाल में स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता भी थे।

वकील के रूप में चितरंजन दास ने भारतीय राजनैतिक आरोपियों की पैरवी और ब्रह्माबंधाब उपाध्याय और भूपेंद्रनाथ दत्ता जैसे क्रांतिकारियों की पैरवी की जिन पर देशद्रोह का आरोप था। उन्हें साल 1908 में प्रसिद्धि मिली जब उन्होंने अलीपुर बम मामले में अरबिंदो घोष की सफल पैरवी कर उन्हें सजा से बचाया। वे क्रांतिकारियों के लिए मुकदमा तो लड़ते थे, लेकिन उनसे फीस नहीं लेते थे।

वकालत में दास सफल तो रहे लेकिन उन्हें अंग्रेज और उनका शासन बहुत नापसंद था। शुरुआत में वे बंगाल की मशहूर क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति में भी सक्रिय रहे। इसके साथ वे वकालत और पत्रकारिता भी करने लगे। 1917 में उन्होंने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया और वहां भी सफल रहे, लकिन उनका राजनैतिक सफल कम समय तक रहा। उस समय के तिकड़ी लाल बाल पाल में से दास बिपिन चंद्र पाल के बहुत ही करीबी थे। उन्होंने एनी बेसेंट को कांग्रेस अध्यक्ष बनवाने में अहम भूमिका निभाई। दास स्वदेशी के विचार से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उन्होंने बंगाल में गांवों के पुनर्निर्माण , स्थानीय स्वशासन की स्थापना, और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए काम किया।

1920 गांधी जी की असहयोग आंदोलन में भी दास ने सक्रियता दिखाई। उन्हें अपनी आलीशान जीवनशैली छोड़ खादी को अपनाया और बंगाल में कई जगह ब्रिटिश कपड़ों का बहिष्कार किया। इस दौरान वे अपनी पत्नी और बेटे के साथ छह महीने के लिए जेल भी गए थे। उसी साल उन्हें अहमदाबाद अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया।

1922 में महात्मा गांधी ने चौरी चौरी कांड के बाद जब असहयोग आंदोलन बंद करने का ऐलान किया और दास ने उनका विरोध किया। दिसंबर 1922 में गया अधिवेशन में एक बार फिर कांग्रेस के अध्यक्ष बने लेकिन उनके असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अस्वीकृत होने के कारण उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और मोतीलाल नेहरू के साथ कांग्रेस में ही स्वराज पार्टी की स्थापना की।

खादी अपनाते समय ही दास ने अपने सारी संपत्ति एक मेडिकल कॉलेज के नाम दान कर दी और देशसेवा में अपने जीवन के अंतिम समय तक लगे रहे। उनके इस त्याग और देशभक्ति के चलते ही उन्होंने देशबंधु कहा जाने लगा था। अपने जीवन के अंतिम समय में उन्हें स्वास्थ्य का साथ नहीं मिला और 16 जून 1925 को बीमारी की वजह से उनक निधन हो गया।

पाकिस्तान में चुनाव की पैंतरेबाजी

बिक्रम उपाध्याय

पाकिस्तान में आम चुनाव की तारीख आ गई है। अगले साल 8 फरवरी को चुनाव होंगे। चारों सूबों और नेशनल एसेंबली के चुनाव वहां एक साथ होते हैं। अब चुनाव की तारीख तो मिल गई, लेकिन पैंतरेबाजी आगे भी जारी रहेगी। चुनाव को टालने और कुछ पार्टियों के मुताबिक तारीख बढ़ाने के लिए पहले ही बहुत पैंतरेबाजी हो चुकी है। पाकिस्तान के संविधान में यह प्रावधान है कि नेशनल एसेम्बली को भंग किए जाने के 90 दिनों के भीतर चुनाव हो जाने चाहिए। पीडीएम के नेतृत्व में बनी सरकार ने 9 अगस्त 2023 को नेशनल एसेम्बली को भंग करने की सिफारिश कर दी थी। कायदे से 9 नवंबर 2023 तक चुनाव हो जाना चाहिए, लेकिन यह डेट टल जाए इसके लिए तमाम पैंतरे आजमाए गए।

सबसे पहले यह विवाद उत्पन्न किया गया कि आखिर पाकिस्तान में चुनावों की तिथि घोषित करने का अधिकार किसके पास है। पाकिस्तान में यह काम राष्ट्रपति के जिम्मे आता है और राष्ट्रपति राशिद अल्वी ने कम से कम तीन मौकों पर यह कोशिश की कि मुख्य चुनाव आयुक्त को बुलाकर सलाह मशविरा से चुनाव की तिथि घोषित कर दी जाए। लेकिन चुनाव आयोग ने जानबूझ कर राष्ट्रपति की सलाह और उनके निवेदन को ठुकरा दिया और दलील दी कि चुनाव की तारीख तय करने का अधिकार उसी का है और वह इस मामले में राष्ट्रपति की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। अब उसी चुनाव आयोग ने 2 नवंबर 23 को राष्ट्रपति से मिलने अपने अधिकारियों को भी भेजा, उनकी सलाह भी मांगी और उन्हें 8 फरवरी को चुनाव कराने के ऐलान करने का अनुरोध भी किया। सवाल यह उठता है कि फिर यह पैंतरेबाजी क्यों की गई?

चुनाव टालने के हर जतन का कारण एक ही था और वह था नवाज शरीफ की वतन वापसी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग यह चुनाव केवल और केवल नवाज शरीफ को आगे रखकर लड़ना चाहती है और वह इलाज के नाम चार साल से लंदन में रह रहे थे। उनकी वापसी को आसान बनाए बगैर और उन पर अदालती रोक को हटाने का इंतजाम किए बिना मुस्लिम लीग चुनाव में जाने को तैयार नहीं थी।

नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के लिए तीन शर्तें थीं। पहला यह कि उनके मन मुताबिक कोई केयरटेकर सरकार बन जाए, दूसरा तहरीक ए इंसाफ के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को रास्ते से हटा दिया जाए और तीसरा पाकिस्तान में उनकी पसंद के चीफ जस्टिस की नियुक्ति हो जाए।

पीडीएम सरकार के मुखिया नवाज के छोटे भाई शहबाज शरीफ थे और उनके साथ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और कुछ अन्य पार्टियां सहयोग कर रही थी। यानि सभी प्रमुख फैसले पीएमएलएन के नेता कर रहे थे। इसलिए मुल्क में केयर टेकर सरकार भी उन्हीं के मुताबिक बन गई। फिर इस सरकार के पीछे सेना का पूरा हाथ है और सेना इमरान खान को राजनीति से किनारे करने की हर मुमकिन कोशिश में सहयोगी है। इसलिए केयर टेकर सरकार वही कर रही है जो अब नवाज शरीफ कह रहे हैं। पंजाब के केयरटेकर मुख्यमंत्री ने नवाज शरीफ के खिलाफ अदालत के फैसलों को भी निलंबित कर दिया। यानि उनके लिए चुनाव में प्रचार के सभी रास्ते खोल दिए।

सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इस समय जेल में हैं। उन पर चुनाव आयोग ने प्रतिबंध भी लगा रखा है। उनके खिलाफ कम से तीन मामलों में कभी भी फैसले आ सकते हैं। एक तोशाखाना से सामान चुराकर बेचने का, अमेरिका के साइफर को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने का और तीसरा 9 मई को सेना के प्रतिष्ठानों पर हमले करने के आरोपों का। तीनों केस में सुनवाई जारी है और फैसलों का इंतजार किया जा रहा है।

नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को जब पाकिस्तान आए तो परिस्थितियां उनके अनुकूल हो चुकी थी। 16 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे से जस्टिस बांदियाल रिटायर हो चुके थे। उनकी जगह जस्टिस काजी फैज ईसा चीफ जस्टिस का पद संभाल चुके हैं। पूरी ज्यूडिशियरी में इस बात का संदेश पहुंचाया जा चुका है कि नवाज शरीफ के साथ किस तरह से पेश आना है।

21 अक्टूबर को जब नवाज शरीफ इस्लामाबाद पहुंचे तो कोर्ट से उन्हें बिना किसी परेशानी के जमानत दे दी गई। जबकि वह एक फरार मुजरिम की कैटेगरी में थे। उनके खिलाफ अन्य मामलों में भी पूरी तरह नरमी बरते जाने के आसार हैं। अलअंजिजिया और एवनफील्ड केस के मामले में सुनवाई तेजी से कराने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि उनके प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाए। इस मामले में खास भूमिका नैब की है, जो इस समय पूरी तरह सरेंडर किए हुए है।

पाकिस्तान में खेल अब नवाज शरीफ बनाम अन्य हैं। हाल तक सरकार में साथ रहने वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और मौलाना फजल उर रहमान अब पीएमएलएन के साथ नहीं है। कहा तो यह भी जा रहा है कि सेना और अदालतों के हस्तक्षेप से नवाज शरीफ को यदि किसी प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाए जाने की कोशिश हुई तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इमरान खान से भी हाथ मिला सकती है। इस मामले में दोनों पार्टियों के अन्य नेताओं की बैठकें हो रही हैं। पीपीपी अभी से ही लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की शिकायत कर रही है। खैर पाकिस्तान की राजनीति किसी साइंस का विषय नहीं है। इसमें इतने किरदार हैं और परिस्थितियां इतनी जल्दी बदल जाती हैं कि कोई भी कयास लगाना आसान नहीं है।

हिन्द स्वराज्य

छुटकारा (भाग-5)

गतांक से आगे...

6. जो डॉक्टर होते हुए भी अपना पेशा छोड़ेगा और समझेगा कि लोगों की चमड़ी चोंथने के बजाय बेहतर है कि उनकी आत्मा को छुआ जाय और उसके बारे में शोध- खोज करके उन्हें तंदुरुस्त बनाया जाय। 7. जो डॉक्टर होने से समझेगा कि खुद चाहे जिस धर्म का हो, लेकिन अंग्रेजी वैद्यक शालाओं—फार्मेसियों—में जीवों पर जो निर्दयता की जाती है, वैसी निर्दयता से (बनी हुई दवाओं से) शरीर को चंगा करने के बजाय बेहतर है कि शरीर रोगी रहे। 8. जो डॉक्टर होने पर भी खुद चरखा चलायेगा और जो लोग बीमार होंगे उन्हें उनकी बीमारी का सही कारण बताकर उसे दूर करने के लिए कहेगा; निकम्मी दवाएँ देकर उन्हें गलत लाड़ नहीं लड़ायेगा। वह तो यही समझेगा कि निकम्मी दवाएँ न लेने से बीमार की देह अगर गिर भी जाय, तो उससे दुनिया अनाथ नहीं हो जायेगी, और यही मानेगा कि उसने बीमार पर सच्ची दया की है। 9. जो धनी होने पर भी धन की परवाह किये बिना अपने मन में होगा वही कहेगा और बड़े-से-बड़े सत्ताधीश की भी परवाह न करेगा। 10. जो धनी होने से अपना रुपया चरखे चालू करने में खरचेगा और खुद सिर्फ स्वदेशी माल का इस्तेमाल करके दूसरों को भी ऐसा करने के लिए बढ़ावा देगा। 11. दूसरे हर हिन्दुस्तानी की तरह जो यह समझेगा कि यह समय पश्चात्ताप का, प्रायश्चित का और शोक का है। 12. जो दूसरे हर हिन्दुस्तानी की तरह यह समझेगा कि अंग्रेजों का कसूर निकालना बेकार है। हमारे कसूर की वजह से वे हिन्दुस्तान में आये, हमारे कसूर के कारण ही वे यहाँ रहते हैं और हमारा कसूर दूर होगा तब वे यहाँ से चले जायेंगे या बदल जायेंगे। 13. दूसरे हिन्दुस्तानियों की तरह जो समझेगा कि मातम के वक्त मौज- शौक नहीं हो सकते। जब तक हमें चैन नहीं है तब तक हमारा जेल में रहना या देश निकाला भोगना ही ठीक है। 14. जो दूसरे हिन्दुस्तानियों की तरह यह समझेगा कि लोगों को (समझाने के बहाने जेल में न जाने की खबरदारी रखना निरा मोह है। 15. जो दूसरे हिन्दुस्तानियों की तरह यह समझेगा कि कहने से करने का असर अद्भुत होता है; हम निडर होकर जो मन में है वही कहेंगे और इस तरह कहने का जो नतीजा आये उसे सहेंगे, तभी हम अपने कहने का असर दूसरों पर डाल सकेंगे। **क्रमश: ...**

सामाजिक आंदोलनों के आगे लड़खड़ाती राजनीति

अमिताभ श्रीवास्तव

तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं,
कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं

सुप्रसिद्ध शायर दुष्यंत कुमार का यह शेर महज एक समाज के आंदोलन से हुए बवाल के दौरान राजनेताओं की स्थिति पर याद आ गया, जिन्हें अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागना पड़ रहा था। इस आक्रोश के बीच सहानुभूति के दो शब्द भी आम आदमी के पास नहीं थे। आगे इसी वातावरण के बीच ही जब बीते बुधवार को मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई तो उसमें 32 दलों के नेताओं का सहज ही पहुंच जाना किसी आश्चर्य से कम नहीं था।

इसके अलावा कुछ नेताओं का बैठक में न बुलाने पर दर्द भी यूं ही नहीं उभरा था। स्पष्ट था कि पिछले दिनों आक्रामक हुआ मराठा आरक्षण आंदोलन किसी भी राजनीतिक दल को अलग कर नहीं देख रहा था। हताशा में उसके कार्यकर्ता जिस तरह सुरक्षा के लिए चुनौती बन रहे थे, उससे हर नेता के माथे पर बल पड़ रहा था जिसके फलस्वरूप समस्त प्रकार की आलोचना करने वाले नेता बिना किसी मान-मनौव्वल के सरकार के दरवाजे पर पहुंच गए थे।

भारत में सामाजिक आंदोलनों का इतिहास नया नहीं है। देश के ज्यादातर राज्यों में समाज की समस्याओं को लेकर आंदोलन हो चुके हैं। उन्हें व्यापक समर्थन भी मिला है गुजरात में पाटीदार समाज हो या फिर राजस्थान में जाट, गुर्जर आंदोलन या कर्नाटक में लिंगायत समाज का आंदोलन हो, सभी जगह सरकार को लोहे के चने चबाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन सभी आंदोलनों की शुरुआत में विपक्ष के नेताओं ने भले ही सरकार के खिलाफ आंदोलन समझ कर उन्हें हल्के में लेने की भूल की, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ में आया कि इनकी आंच उन तक भी पहुंच रही है। दरअसल सभी आंदोलनों की तह में जाकर देखा जाए तो उनके पीछे अनेक

ठोस कारण नजर आते हैं, जिन्हें तत्कालीन सरकारों ने समय पर सुलझाने की जगह आश्वासनों से लोगों को बरगलाने की कोशिश की कुछ मामलों में भूल या लापरवाही को लंबे समय तक सुधारा नहीं गया।

किंतु जब कभी उनको लेकर आवाज उठी है तो निश्चित ही वह राजनीतिक दलों के पास पहुंची। वे समय और परिस्थिति को भांपकर श्रेय लेने की कोशिश में आंदोलनों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहारा देने लगे। जब कोई दल सत्ता में रहा तो उसने संविधान और कानून का हवाला देकर नियमों की बात की वहीं जब कोई दल सत्ता से बाहर रहा तो वह संविधान और कानून से परे जाकर वादे पूरे करने या करवाने का वादा करता रहा, जिसका नतीजा एक उम्मीद बंधने के रूप में सामने आया। मगर जब उम्मीद टूटी तो गुस्सा भी राजनीतिक दलों पर फूटा, जिसे अनुचित नहीं ठहराया जा सकता. साफ है कि समाज के नाम पर वोट की राजनीति कब तक लोगों की भावनाओं और मजबूरियों की कीमत पर चलाई जा सकती थी।

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा वर्ष 1968 से चर्चा में रहा और अस्सी के दशक में अण्णासाहब पाटील ने उसे विधिवत उठाया। उसके बाद अनेक आयोग, समिति, सुनवाई होती रहीं सभी दलों की सरकारें आती रहीं व जाती रहीं, लेकिन मूल समस्या का मराठा समाज को समाधान नहीं मिला। उसके जीवन स्तर में लगातार गिरावट ही आती रही। समाज के चंद लोगों की आड़ में बड़े वर्ग को नजरअंदाज किया जाता रहा हालांकि प्रलोभनों की आड़ में अनेक नेताओं ने अपनी राजनीति जरूर चमका ली। यहां तक कि उनकी संस्थाओं और संस्थानों में दिन दूनी-रात चौगुनी प्रगति भी हुई। किंतु जिस विषय से बात आरंभ हुई थी, वह वहीं पर रुककर अपनी बारी का इंतजार करती रही। अब जब आंदोलनकारियों ने आक्रामक रूप अपना लिया है, तो संकट के बादल सभी के सिर पर मंडराने लगे हैं। लंबी खींचतान के बाद बनी जटिल स्थितियों से समस्या का हल भी आसानी से नहीं मिल सकता है इसलिए राजनीति के बड़े वर्ग को खामोशी में ही भलाई दिख रही है।

यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि भारतीय राजनीति में चुनाव के दौरान मतों का बंटवारा धर्म, जाति, पंथ के नाम पर आसानी से हो जाता है, बावजूद इसके कि वह आचरण आदर्श चुनाव आचार संहिता के विरुद्ध है। हर राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार का चयन उसकी योग्यता से अधिक क्षेत्र के धार्मिक और जातिगत समीकरणों के आधार पर करता है। उसे विश्वास रहता है कि उम्मीदवार की निजी पहचान मतदान में सहायक सिद्ध होगी किंतु मतदाता के मन में अपनी जाति या धर्म के उम्मीदवार से अपेक्षा अपने अधिकारों को दिलाने, समस्याओं का निराकरण कराने के लिए अधिक रहती है।

वे मानते हैं कि उनके बीच का उम्मीदवार उनकी समस्याएं जल्द सरकार तक पहुंचाएगा और हल भी ढूंढ़ कर निकाल लाएगा मगर चुनाव के बाद बनते सत्ता के समीकरण सरकार चलाने के लिए केंद्रित हो जाते हैं। परंतु नेता समाज को अगले चुनाव से पहले याद करने की कोशिश नहीं करते हैं। जिससे राजनीतिज्ञों को लेकर कुंठा बढ़ती है तो राजनीति से परे एक समाज आंदोलन को शुरू होने की वजह मिलती है। उसमें ज्यादातर सम विचारी- सम दुःखी-पीड़ित लोग शामिल होते हैं। यदि वे संगठित रहे तो सरकार की नाक में दम करके ही रहते हैं। अनेक राज्यों में इस तरह के दृश्य निर्मित हुए। इससे भी आगे निराशा का भाव लोगों के मन में अधिक घर कर गया तो मराठा आंदोलन की तरह स्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिसमें राजनीति लड़खड़ाने लगती है. महाराष्ट्र का ताजा राजनीतिक परिदृश्य कुछ इसी संकट से गुजर रहा है और आने वाले दिन उसके मुश्किल में ही गुजरने की संभावना है।

सवाल यही है कि राजस्थान में जाटों के नेता सरकार में थे। गुजरात में पाटीदार नेता सरकार का हिस्सा थे। कर्नाटक में लिंगायतों का सत्ता पर दबदबा था। महाराष्ट्र में मराठा छत्रपों के इर्द-गिर्द ही राजनीति घूमती है। ऐसे में भी समाज का भरोसा नहीं होना, समाज से ही बने नेताओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है। उनके वादे और समाज के उत्थान के प्रति ईमानदारी पर प्रश्नचिह्न खड़े करता है। इसमें सत्ता के लिए समाज का इस्तेमाल दिखाई देता है। इसी कारण राजस्थान हो या गुजरात या फिर ताजा उदाहरण महाराष्ट्र है, जहां से समाज की आड़ में राजनीति करने वालों को सीधा संदेश मिला है। जिसमें स्पष्ट है कि समस्याओं को लंबे समय तक दबाना, छिपाना या बहलाना अब लंबे समय तक नहीं चल सकता है। उसमें प्रतिशोध की भावना पनपने लगती है. शायर दुष्यंत कुमार भी कहते हैं-

पक गई हैं आदतें बातों से सर होंगी नहीं,
कोई हंगामा करो ऐसे गुज़र होगी नहीं... !

इसलिए यदि मराठा समाज आर-पार की लड़ाई के लिए सामाजिक आंदोलन के रूप में तैयार है तो कोई आश्चर्य का विषय नहीं, मुश्किल तो उसके आगे स्थापित नेताओं की राजनीति के लड़खड़ाने की है, जिसे आगे भी कुछ और आंदोलनों का सामना करना पड़ेगा।

क्या मध्यप्रदेश में नर्मदा भी बनेगा सियासत का बड़ा मुद्दा!

आशीष तिवारी

मध्य प्रदेश की सियासत में नदियों का कितना रोल है इसका अंदाज यहां बहने वाली नर्मदा और उसके मुद्दों से समझ सकते हैं। इस चुनाव में नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए शहर के लोगों ने इसका मुद्दा प्रमुखता से उठाना शुरू कर दिया है। लोगों की मांग है कि नर्मदा में शहरों के सीवर का पानी लगातार गिर रहा है, लेकिन किसी भी स्थानीय नेता और राजनीतिक दलों ने आज तक इस संबंध में कोई भी आवाज बुलंद नहीं की है। अमर उजाला डॉट कॉम से नर्मदा नदी के तट पर होने वाली 'आरती महासंघ' और स्थानीय लोगों ने मैली हो रही नर्मदा के जिम्मेदारों पर जमकर भड़ास निकली। लोगों ने बताया कि नर्मदा नदी को लेकर राजनीतिक

पार्टी और नेताओं का रवैया शून्य है। हालांकि, इस बार स्थानीय लोगों ने खास तौर से नर्मदा नदी के प्रति आस्था रखने वालों ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित तिलवारा घाट में लोगों को मैली हो रही नर्मदा लेकर जिम्मेदारों के प्रति जबरदस्त नाराजगी देखी। तिलवारा घाट पर होने वाली आरती करने वाले पुजारी के समूह के संयोजक राहुल तिवारी कहते हैं नर्मदा के इस घाट को किसी भी नेता ने आज तक गंभीरता से नहीं लिया। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश की जीवनदायनी इस नर्मदा नदी में शहर का सीवर गिरता है, लेकिन किसी भी नेता ने आज तक यह जहमत नहीं उठाई की इसके लिए कुछ किया जाए। राहुल कहते हैं कि यह तो नर्मदा के पानी की तेज रफ्तार के चलते सारी गंदगी तो बह जाती है, लेकिन नदी होती तो अपवित्र ही है। स्थानीय निवासी और दिवस समुदाय के युवा नेता अजय केवट कहते हैं कि स्थानीय नेताओं और पार्टियों को लगता है कि नर्मदा नदी में बहने वाली गंदगी कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। पर हकीकत यही है नर्मदा नदी के तटों पर बसे हुए शहरों के लोगों के लिए यह बहुत बड़ा मुद्दा है। अजय कहते हैं कि उनके समुदाय के लोगों ने लगातार नदियों में गंदगी को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि और राजनीतिक दलों के सामने अपनी बात रखी है। लेकिन आज तक कभी भी इस और कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उनका कहना है कि नर्मदा नदी को लेकर की जाने वाले वाली बेरुखी पर इस विधानसभा के चुनाव में कई सीटों के नतीजे तक बदले जा सकते हैं। नर्मदा नदी की सफाई को लेकर अभियान चलाने वाली संस्था नर्मदा बचाओ के जगत पुंडीर कहते हैं कि दोनों को लगता है की नदी कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता। यह सोचना ही राजनीतिक दलों और सियासतदानों की भूल साबित हो सकती है। उनका कहना है कि सिर्फ जबलपुर ही नहीं बल्कि नदी के किनारे बसे हुए और शहरों की ओर से नदी में लगातार गंदगी बढ़ती जा रही है। लेकिन इस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। नर्मदा बचाओ समिति के अजय शर्मा का कहना है कि घाटों पर साफ सफाई को लेकर न नगर निगम और न अन्य जिम्मेदार अथॉरिटी कोई काम कर रहे हैं। हालांकि नर्मदा नदी की साफ सफाई अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय सांसद राकेश सिंह का कहना है कि वह लगातार नर्मदा की साफ सफाई को लेकर न सिर्फ अभियान चलाते हैं बल्कि उसके लिए हर संभव प्रयास भी करते हैं। इसी दौरान घाट पर मौजूद कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष श्याम सोलंकी कहते हैं कि उनके मेयर ने जबलपुर के सभी घाटों की साफ-सफाई और उसके बजट के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। घाटों पर हो रही सफाई और विकास को दिखाते हुए कहते हैं कि जो सड़कें आज तक नहीं बनी थी उनको अब उनके मेयर बनवा रहे हैं। वह दावा करते हैं कि सिर्फ जबलपुर ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो पूरे मध्य प्रदेश की जीवनदायनी नर्मदा मां को और व्यवस्थित सुसज्जित तरीके से संवारा जाएगा।

दारा सिंह और राजभर पर कम नहीं हुआ है भाजपा का विश्वास

स्वदेश कुमार

राजनीति में एक हार से सब कुछ खत्म और एक जीत से सब कुछ हासिल नहीं हो जाता है। जीत-हार राजनीति का हिस्सा है। यह अनवरत जारी रहता है। इस बात का अहसास उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाओं के चलते किया जा रहा है। चर्चा है कि योगी सरकार में कुछ और नये चेहरे शामिल होने वाले हैं जिससे लोकसभा चुनाव में जातीय समीकरण का फार्मूला फिट हो सके। इसीलिए योगी मंत्रिमंडल में दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाये जाने की चर्चा हो रही है। यह वह दो नेता हैं जिनको भाजपा का जातीय समीकरण मजबूत करने के लिए

हाल फिलहाल में पार्टी के साथ जोड़ा गया था। ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ बीजेपी का गठबंधन हुआ था और घोसी से सपा विधायक दारा सिंह चौहान सपा की सदस्यता और विधायिकी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन यह भी हकीकत है कि बीजेपी के बैनर तले घोसी से उप चुनाव लड़े दारा सिंह को हार का समाना करना पड़ा था। वहीं ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की बात की जाये तो विधान सभा चुनाव में बीजेपी को ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से उतना फायदा नहीं मिला था, जितनी उनसे उम्मीद थी, मगर बीजेपी ने आस नहीं छोड़ी है, उसे आज भी दारा सिंह और राजभर पर भरोसा है। माना जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान द्वारा इन दोनों नेताओं को दिवाली से पहले योगी मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए जल्द फैसला लिया जा सकता है। सब कुछ ठीकठाक रहा तो सपा का साथ छोड़कर एनडीए में आए सुभासपा के मुखिया ओपी राजभर को कैबिनेट के अलावा दारा सिंह चौहान को भी मंत्री पद दिया जा सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे में केंद्रीय नेताओं से मुलाकात के बाद से ऐसे कयास लग रहे हैं। हालांकि, इस बात की पुष्टि नहीं हुई है लेकिन माना जा रहा है कि दोनों नेताओं को योगी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। राजभर को एनडीए में और दारा सिंह चौहान को बीजेपी में शामिल होने से पहले पार्टी के नेताओं ने मंत्री पद देने का आश्वासन दिया था। हालांकि, घोसी में हुए उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद से दोनों ही नेताओं को मंत्री पद मिलने की राह थोड़ी कठिन हो गई थी। उधर, ओपी राजभर ने दावा किया है कि दिवाली से पहले बीजेपी इसकी घोषणा कर सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर सपा के पीडीए और जाति जनगणना के मुद्दे की काट खोज रही बीजेपी के लिए यह दोनों नेता काफी अहम माने जा रहे हैं।

राजस्थान में कांग्रेस-भाजपा पर चढ़ा भगवा रंग

विनोद पाठक

राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब भगवा रंग चढ़ने लगा है। वैसे तो भगवा पर भाजपा पहला अधिकार मानती है, लेकिन इस बार कांग्रेस भी पीछे नहीं है। पार्टी ने जहां साधु-संतों को चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस की भी कोशिश है कि वो संत समाज से कुछ चेहरों को पाले में लेकर आए। भाजपा के साथ कांग्रेस प्रत्याशी भी मंदिरों से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि वो भी वोटरों के बीच हिंदूवादी नजर आएं।

भाजपा की उम्मीदवारों की पहली सूची में अलवर से सांसद महंत बालकनाथ को तिजारा सीट से टिकट दिया गया। महंत बालकनाथ नाथ संप्रदाय से आते हैं। नाथ को जिस तिजारा सीट से मैदान में उतर गया है, वहां ध्रुवीकरण होता आया है। महंत बालकनाथ के नामांकन के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे और उन्होंने तालिबान से लेकर हनुमान की गदा तक का जिक्र किया।

एक तरह से योगी आदित्यनाथ से एक टोन चुनावों के लिए सेट कर दी। भाजपा ने पोखरण सीट से महंत प्रतापपुरी को टिकट दिया है। महंत प्रतापपुरी वर्ष 2018 के चुनाव में इस सीट पर चंद वोटों से हार गए थे।

इस सीट पर भी ध्रुवीकरण होता है, क्योंकि यहां से कांग्रेस ने मुस्लिम धर्मगुरु गाजी फकीर के बेटे सालेह मोहम्मद को एक बार फिर टिकट दिया है। वर्ष 2018 में सालेह मोहम्मद ने ही महंत प्रतापपुरी को हराया था और अशोक गहलोत सरकार में मंत्री बने थे। गाजी फकीर का प्रभाव पाकिस्तान तक है।

भाजपा ने सिरोही सीट से ओटाराम देवासी को एकबार फिर टिकट दिया है। देवासी समाज से आने वाले ओटाराम

वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में जीतकर आए थे और वसुंधरा राजे सरकार में उन्हें देवस्थान विभाग का मंत्री बनाया गया था। हालांकि, वो मंत्री रहते हुए मुंडारा स्थित चामुंडा माता मंदिर में पुजारी रहे। मंदिर की करोड़ों रुपए की संपत्तियां हैं और लाखों रुपए का दान आता है।

राजधानी जयपुर की हवामहल सीट से भाजपा ने बालमुकुंद आचार्य को टिकट दिया है। बालमुकुंद आचार्य कुछ दिन पहले तक टिकटों की दौड़ में कहीं नहीं थे, लेकिन महीनाभर पहले वो एकाएक हवामहल क्षेत्र में मंदिरों को तोड़ने को लेकर सक्रिय हुए। उन्हें विश्व हिंदू परिषद का भी साथ मिला। वो बालाजी हाथोज धाम के महंत हैं। मात्र एक महीने की सक्रियता पर उन्हें टिकट मिल गया है। यह भी माना जा रहा है कि वो न केवल हवामहल, बल्कि किशनपोल, आदर्श नगर और सिविल लाइंस सीट पर भी हिंदू वोटों को साधने का काम करेंगे। पार्टी ने अभी पश्चिमी राजस्थान की पचपदरा सीट से प्रत्याशी घोषित नहीं किया है और यहां पर भजन गायक प्रकाश माली दावेदारी जाता रहे हैं। खास बात यह है कि संत समाज भी भाजपा पर लगातार अधिक से अधिक संतों को टिकट देने का दबाव बनाता रहा है।

भगवा ध्वज उठाने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने भाजपा से टिकट की कोशिश कर रहीं साध्वी अनादि को पार्टी में शामिल कराया है। सिंधी समाज से आने वाले साध्वी अनादि की ज्वाइनिंग के समय न केवल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, बल्कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद थे।

पिछले दिनों पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपने नामांकन से पहले टोंक के भूतेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। इसी तरह कई और प्रत्याशी भगवा पट्टा डालकर नामांकन करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी राजस्थान में मंदिरों के दर्शन कर चुके हैं।

कुल मिलाकर गहलोत सरकार को तुष्टीकरण के मुद्दे पर घेरने वाली भाजपा को कांग्रेस भी हिंदुत्व के मुद्दे पर टक्कर देने की कोशिशों में जुटी है। स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार कह चुके हैं कि क्या हम हिंदू नहीं हैं? गहलोत सरकार में मंत्री और सिविल लाइंस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास खुद को भगवान राम का वंशज बता रहे हैं। अब देखना है कि हार्डकोर हिंदुत्व वाली भाजपा और सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रही कांग्रेस में से प्रदेश की जनता किसे पसंद करती है?

फोन 'हैक' की राजनीति कभी भी सत्ताधारी दल के लिए फायदे का सौदा नहीं रही है

ललित गर्ग

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के लगातार आक्रामक होने के मध्य में देश के कुछ प्रमुख विपक्षी नेताओं के आईफोन पर निगरानी किये जाने का मामला एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर रहा है। इसे सरकार प्रायोजित बताकर सरकार को घेरने की कोशिशें भी एकाएक उग्र हो गयी है। एप्पल कम्पनी ने इन फोन धारकों को ईमेल सन्देश भेज कर लिखा है कि आपके फोन को किसी 'मालवेयर वायरस' से सरकार द्वारा सर्वेक्षण में रखा जा रहा है जिसके माध्यम से आपकी सारी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। मगर इसके साथ ही सरकार ने ऐसी किसी कार्रवाई से इन्कार करते हुए पूरे मामले की सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्रालय की संसदीय समिति से जांच कराने की घोषणा कर दी है और कहा है कि ऐसा ही एक ई-मेल सन्देश वाणिज्य मन्त्री पीयूष गोयल को भी आया है। फोनों पर निगरानी का आरोप सरकार के लिए भी गंभीर चिन्ता का विषय है क्योंकि यह ऐसा मामला है जिसमें सत्ता से बेदखल होने जैसी स्थितियां बनती हैं। जब तक मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती, किसी को भी दोषी ठहराना जल्दीबाजी होगी। पक्ष-विपक्षी दल चुनावी माहौल को धुंधलाने या विवादास्पद बनाने की बजाय उसे स्वस्थ बनाने में सहयोग करें, यह स्वस्थ एवं आदर्श लोकतंत्र की बुनियाद है। किसी की स्वतंत्रता का हनन लोकतंत्र की पवित्रता को ही समाप्त कर देती है।

निश्चित ही किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की ओर से विपक्षी नेताओं की निजता भंग करने का कोई भी मामला सामने आता है, तो स्वाभाविक ही सरकार को घेरा जाना चाहिए एवं जवाब मांगा जाना चाहिए। लेकिन बिना बुनियाद के ऐसे विवाद खड़े करना उचित नहीं है। अच्छी बात इस मामले में यह है कि सरकार ने इन आरोपों को पूरी गंभीरता से लिया है और तत्परता से निर्णय लेते हुए न केवल पूरे मामले की विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं बल्कि आईफोन कंपनी से भी जांच में शामिल होने को कहा गया है। सभी पक्षों के लिए जरूरी है कि निष्कर्ष निकालने की जल्दबाजी करने के बजाय मामले की बारीक और विश्वसनीय जांच सुनिश्चित करने में सहयोग करें। यह न केवल विपक्षी दलों के नेताओं की निजता से जुड़ा मामला है बल्कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा एवं प्रतिबद्धता का भी मामला है।

हालांकि यह साफ करना भी जरूरी है कि मौजूदा मामले में अभी बात सिर्फ संदेह की है। आईफोन पर ऐपल की ओर से भेजे गए ये मेसेज ऑटो जेनेरेटेड थे, जिनकी प्रामाणिकता को लेकर कंपनी भी आश्वस्त नहीं है। उसका कहना है कि इनमें से कुछ मेसेज फॉल्स अलार्म के भी हो सकते हैं। इसके बावजूद विपक्षी नेताओं की आशंकाएं निराधार हैं या आधारभूत हैं, यह तो जांच के निष्कर्षों से ही पता लगेगा। मेसेज विपक्षी दलों के नेताओं और कुछ सत्ता विरोधी माने जाने वाले पत्रकारों के ही फोन पर आने का आरोप निराधार है क्योंकि ऐसा ही मेसेज एक केन्द्रीय मंत्री को भी मिला है। सूचना टैक्नोलॉजी क्रान्ति होने के बाद चीजें काफी बदल चुकी हैं अतः आरोपों का स्वरूप भी बदल चुका है। इससे पहले दो वर्ष पूर्व भी देशवासियों ने 'पेगासस' वायरस का पूरा कर्मकांड देखा है जिसकी जांच सर्वोच्च

न्यायालय द्वारा गठित एक विशेष समिति ने की थी। इस मामले को लेकर दो साल पहले संसद में भी जमकर हंगामा हुआ था। लेकिन उसमें आरोप सिद्ध नहीं हो पाये थे। ऐसे में जब विपक्षी नेताओं के फोन की हैकिंग का यह नया आरोप लगा है तो उसे पूरी गंभीरता से लेने की जरूरत है। इस मामले को लेकर आरोप-प्रत्यारोप से बचते हुए सत्य के उजागर होने तक इंजतार करना चाहिए। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि वह पूरे प्रकरण की जांच में एप्पल कम्पनी के उच्च पदाधिकारियों को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। इस मामले में मूल सवाल निजी स्वतन्त्रता का उठता है जिसे सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों का मूल अधिकार मान चुका है। लोकतांत्रिक प्रणाली में सभी को लिखने, बोलने, सोचने और करने की स्वतंत्रता होती है।

आईटी मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय ऑनलाइन सुरक्षा एजेंसी सीईआरटी-इन (भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम) आईफोन 'हैकिंग' प्रयासों के विपक्ष के दावे की जांच करेगी और वही हैकिंग और फ़िशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों का जवाब देने के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय एजेंसी है। महुआ मोइत्रा, प्रियंका चतुर्वेदी, राघव चड्ढा, शशि थरूर, पवन खेड़ा और सीताराम येचुरी सहित कई विपक्षी नेताओं ने मंगलवार को दावा किया कि उन्हें एप्पल अलर्ट मिला है जिसमें उनके आईफोन में राज्य प्रायोजित हैकिंग की चेतावनी दी गई है। आईफोन निर्माता एप्पल ने मंगलवार को कहा था कि वह विपक्षी दलों के कुछ सांसदों को भेजे गए चेतावनी संदेश को किसी विशिष्ट सरकार-प्रायोजित सेंधमारों से नहीं जोड़ती और वह इस बारे में जानकारी नहीं दे सकती है कि ऐसी चेतावनियों का कारण क्या है। कारणों का पता तो विस्तृत जांच के बाद ही सामने आयेगा, तब तक पक्ष एवं विपक्ष को शांत रहते हुए विवेक का परिचय देना चाहिए। क्योंकि यह भारत, भारतीय लोकतंत्र एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था के व्यवस्थित संचालन से जुड़ा मामला है। ताजा मामला इसलिये भी बहुत गंभीर है क्योंकि ऐसे मामलों में सत्ताएं बदलती देखी गयी हैं। इसलिये ऐसे मामलों एवं आरोपों में गंभीरता बरतना जरूरी है।

इस तरह के राजनेताओं एवं राजनीतिक दलों के निजता भंग के कम उदाहरण ही भारत में देखने को मिले हैं लेकिन जब भी किसी सरकार पर इस प्रकार के आरोप लगे तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी है। सबसे बड़ा उदाहरण 80 के दशक का है जब कर्नाटक की वीरप्पा मोइली सरकार 'टेप कांड' में फंस गई थी तो उसे सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। डॉ. मनमोहन सिंह सरकार पर भी फोन टेप करने के आरोप लगे थे। पूरी दुनिया का सबसे सशक्त और उदार लोकतन्त्र माने जाने वाले अमेरिका के वाटर गेट कांड में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने अपनी प्रतिद्वन्द्वी डेमोक्रेटिक पार्टी के मुख्यालय पर जासूसी यन्त्र लगा कर उसकी गतिविधियों को जानने की कोशिश की थी। निक्सन भले ही इस मामले पर लम्बी टालमटोल करते रहे हो मगर भारत सरकार ने तो एप्पल फोन कांड का भंडाफोड़ होते ही इसकी जांच कराने की घोषणा कर दूध का दूध, पानी का पानी करने की अपनी संकल्पबद्धता दर्शा दी है। इस हकीकत को भी हमें ध्यान में रखकर ही इस मामले में और टीका-टिप्पणी करनी होगी।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र एक जीवित, निष्पक्ष एवं आदर्श तंत्र है, जिसमें सबको समान रूप से अपनी-अपनी मान्यताओं के अनुसार चलने, गतिविधियों को संचालित करने की पूरी स्वतंत्रता है। लोकतंत्र की नींव ही निजता की सुरक्षा करने के सिद्धान्तों पर टिकी है, इस व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक संविधान के दायरे में स्वयंभू होता है। अतः इस मुद्दे पर विपक्षी नेताओं की चिन्ता वाजिब मानी जा सकती है मगर इसके साथ ही सरकार की तरफ से तत्परता से व्यक्त इस मामले में संलिप्त न होने की साफगोई बयान को भी नजरंदाज नहीं किया जा सकता। यदि सरकार ने इस मामले में तुरन्त कार्रवाई की है तो उसकी नीयत पर भी शक करने की कोई वजह दृष्टिगोचर नहीं होती। सरकार किसी की भी निजता को भंग करने का आरोप स्वयं कर लगता हुआ देख बिन बुलाये संकट को कैसे आमंत्रित कर सकती है? क्योंकि इस तरह का कोई भी काम पूर्ण रूप से असंवैधानिक व गैर कानूनी होती है। ऐसी अराजकता, अव्यवस्था एवं एकाधिपत्य लोकतंत्र का ही विलुप्त कर सकता है।

क्या गाय और राम पार लगाएंगे भूपेश की वैतरणी, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में छीन लिए बीजेपी के मुद्दे?

गाय और राम दो ऐसे विषय हैं जो बीजेपी की चुनावी नोटबुक में सबसे ऊपर रहते हैं। हिंदी बेल्ट के राज्यों में गाय और राम कोर मुद्दों के रुप में सामने आते रहे हैं। यह मुद्दे चुनावों को ध्रुवीकृत करने के साथ बीजेपी को वोट दिलवाते रहे हैं। पर छत्तीसगढ़ के चुनावों में ऐसा नहीं है। राम और गाय यहां मुद्दा तो है लेकिन यह मुद्दा बीजेपी की ओर से ना होकर कांग्रेस की ओर से है। आप गाय और राम का नाम कांग्रेस नेताओं के मुंह से सुनेंगे। कांग्रेस की सभाओं में गाय, गौमूत्र और गाय के गोबर की बात होती है। भगवान राम की बात होती है। मां कौशल्या की बात होती है। सवाल यह है कि गाय और राम के यह मुद्दे भूपेश बघेल को चुनावी लाभ दे सकते हैं।

बीते पांच सालों में भूपेश बघेल सरकार लगातार गाय और राम पर कुछ न कुछ ऐसा करती रही है कि वह विषय के रुप में जनता के बीच जिंदा रहा। अपने इंटरव्यू में भूपेश यह कहते दिखे हैं कि गाय हमारे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा ही नहीं है। यह राज्य किसानों का राज्य है जिसमें पशुओं को सम्मान के साथ देखा जाता है। कांग्रेस पार्टी के लिए भगवान राम और गौ माता विरासत, संस्कृति और सेवा का विषय है। बीजेपी ने इसे राजनीतिक बनाया। भूपेश कहते रहे हैं कि गाय की तरह राम भी हमारे लिए राजनीतिक नहीं हैं। मां कौशल्या का मायका छत्तीसगढ़ में है। यह राज्य भगवान राम का ननिहाल है। उनके साथ इस राज्य का रिश्ता एक परिवार की तरह है। हम इस पर राजनीति नहीं कर सकते। इसके उलट बीजेपी राम के मुद्दे पर शांत है। उसकी सभाओं में राम और गाय पर बात नहीं होती। ऐसे समय जब अयोध्या में मंदिर का निर्माण तेजी के साथ हो रहा है बीजेपी ने इस मसले को चुनावों में नहीं उठाया है। हालांकि अभी बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र नहीं आया है। गौठान और गौमूत्र पर हो सकता है कि बीजेपी के द्वारा भी कोई घोषणा की जाए।

क्या करने की कोशिश है बघेल सरकार की

बीते पांच सालों में भूपेश बघेल की सरकार ने गाय और राम के माध्यम से एक साफ्ट हिंदुत्व की राजनीति की है। इस नए राजनीतिक कोलाज में सरकार ने संस्कृति और छत्तीसगढ़ी अस्मिता को भी जोड़ा है। राज्य के कई सारे त्योहारों को सरकारी स्तर पर मनाया गया है। खुद मुख्यमंत्री आंचलिक त्योहारों को मुख्यमंत्री आवास में मनाते हुए दिखे हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि धर्म और संस्कृति का यह कोलाज बीजेपी को असहज करता रहा है। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक दिवाकर मुक्तिबोध इसे कांग्रेस की बदली हुई राजनीति के तौर पर देखते हैं। मुक्तिबोध कहते हैं कि बाकी राज्यों में राम के नाम से असहज दिखने वाली कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में इसको लेकर बिल्कुल अलग एप्रोच लिया है। वह सारे मुद्दे जो बाकी राज्यों में बीजेपी के वोटरों को धर्म के नाम पर ध्रुवीकृत करते हैं भूपेश ने उन्हें यहां पनपने नहीं दिया। राम और गाय के अलावा हिंदु देवी-देवताओं के सारे कार्यक्रमों में कांग्रेस के नेता और मंत्री शिरकत करते दिखे हैं। भूपेश सरकार ने राम के साथ एक रिश्तेदारी जोड़ने की कोशिश की है। उनकी यह कोशिश कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का छत्तीसगढ़ की राजनीति में किसी भी तरह का लाभ बीजेपी ना ले पाए। यह चुनावी परिणाम बताएंगे कि कांग्रेस यह करने में कितनी सफल रही है।

क्यों जरुरी है राम और गाय कांग्रेस के लिए

राम और गाय कांग्रेस के लिए क्यों जरुरी है इस सवाल पर छत्तीसगढ़ एक समाचार चैनल से जुड़े वरिष्ठ टीवी पत्रकार बरुण सखाजी कहते हैं कि भूपेश सरकार गाय के मामले में सेवा भाव का रुख दिखाया है। प्रदेश में यह मुद्दा राजनीतिक नहीं है। दूसरी ओर राम के मुद्दे को सरकार ने कामयाबी से अपने पाले में कर लिया है। छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ के माध्यम से वह राम के मुद्दे के साथ जुड़ने में कामयाब रही है। राम के साथ ही साथ सरकार ने रायपुर से 20 किलोमीटर दूर माता कौशल्या के जन्मस्थल को भी विकसित किया है। छत्तीसगढ़ को राम का ममियारा माना जाता है। इस लिहाज से राम यहां की रग-रग में बसे हैं। राजनीति में राम का मुद्दा दशकों से है लेकिन छत्तीसगढ़ में राम उस तरह से चुनावी नहीं हैं जैसे बाकी राज्यों में बनते आए हैं।

गाय और राम पर क्या दावे करती है सरकार

- राज्य में संचालित 10,246 गौठानों में चारा-पानी की व्यवस्था
- सड़कों से पशुओं को हटाने पहल, सड़क पर आवारा गाय नहीं दिखतीं
- गोधन न्याय योजना से गौवंश संरक्षण को मिला बढ़ावा
- गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को अब तक 507.14 करोड़ रूपए का भुगतान
- अब तक 123.56 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी, गोबर विक्रेताओं को 247.12 करोड़ रूपए का भुगतान
- गोबर से 32.72 लाख क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट और गौमूत्र से जैविक कीटनाशक का निर्माण
- गोबर से प्राकृतिक 2.17 लाख लीटर प्राकृतिक पेंट का उत्पादन, 353.01 लाख रुपये की आमदनी
- 2 लाख 564 लीटर गौमूत्र खरीदी, 8 लाख 2256 रुपये का भुगतान

गौठान

- 10,246 गौठान संचालित
- गौठान समितियों तथा स्व-सहायता समूह को अब तक 244.95 करोड़ रूपए का भुगतान
- गौठानों में वर्मी कंपोस्ट निर्माण के लिए कुल टांके - 96,386
- गौठान समिति व स्व-सहायता समूहों द्वारा ग्रामीण औद्योगिक पार्क में वर्मी खाद उत्पादन, सामुदायिक बाड़ी, मशरूम उत्पादन, मछली पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन, गोबर से दीया, गमला व अगरबत्ती निर्माण आदि संचालित

भगवान राम बने भांजे राम

- श्रीराम वन गमन पर्यटन परिपथ के तहत 149 करोड़ रुपये की लागत से भांचा राम के स्मृति चिन्हों को सहेजने की पहल प्रथम चरण के तहत 9 स्थानों पर 51 करोड़ 62 लाख रुपये की लागत से निर्माण प्रारंभ, कई स्थानों पर सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार के कार्य पूर्ण
- राम की मां कौशल्या के जन्म स्थान को विकसित करने की शुरुआत

किसी युद्ध से कम नहीं बस्तर का चुनावी रण, बड़ी चुनौती है नक्सल इलाकों में मतदान

सुकमा जिले का ख्याल आने पर आंखों में नक्सलियों का खौफनाक अक्स तैर जाता है। अप्रैल 2010 में यहीं ताड़मेटला में नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 76 जवान बलिदान हुए थे। इसके तीन साल बाद मई 2013 में झीरम घाटी में नक्सलियों ने प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष नेताओं समेत 33 लोगों की नृशंस हत्या कर दी थी। इस घटना ने बस्तर के सियासी समीकरण बदल दिए थे। उसी साल हुए चुनाव में भाजपा यहां 11 से चार सीटों पर आ गई थी और सहानुभूति की लहर ने कांग्रेस को एक से आठ के आंकड़े तक पहुंचा दिया था। तब से यहां कांग्रेस बढ़त पर है। आइए आपको ले चलते हैं बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर से धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र चिंतागुफा तक की यात्रा पर...

जगदलपुर से शुरू सफर का पहला पड़ाव दरभा के पास स्थित झीरम घाटी था। सिंगल रोड पर करीब 36 किमी दूर झीरम घाटी शहीद स्मारक है, जहां नक्सलियों ने वारदात की थी। सोलर लाइटें भी लगा दी गई हैं। दोनों तरफ से पहाड़ी और हरेभरे जंगलों वाला रास्ता बड़ा खूबसूरत है पर खौफ महसूस होता है। दिन में भी गाड़ियां नजर नहीं आतीं। इस क्षेत्र में काफी नजदीक-नजदीक सीआरपीएफ के कैंप हैं। 10-10 जवानों के सेक्शन एक्सप्लोसिव डिटेक्टर डिवाइस और यूबीजीएल (अंडर बैरल ग्रेनेड लांचर) व स्वचालित हथियार समेत लगातार पैदल पेट्रोलिंग करते हैं। तोकापाल, कांगेर घाटी से होते हुए सुकमा तक लगभग 110 किमी के सफर में यही नजारा देखने को मिला।

सुकमा से लगभग 35 किमी आगे हाईवे पर ही दोरनापाल पहुंचकर पहली बार बूथ बने गांव तलाशे। यहां मिले युवक महेश टेकाम ने बताया, चुनाव में कोई उन क्षेत्रों में नहीं जा रहा। बताया कि नक्सलियों ने मतदान का बहिष्कार का एलान कर रखा है। यही नहीं, नेताओं पर हमले बोलने की भी अपील की है। कुछ अखबारों को सूचना देने का काम करने वाले रंजीत ठाकुर ने भी यही बात दोहराते हुए चिंतागुफा जाने से मना कर दिया। हम अकेले ही आगे बढ़ गए। 46 किमी के इस मार्ग पर सीसी रोड निर्माण का काम लगभग पूरा हो गया है। रास्ते पर चार पहिया वाहनों का आना-जाना न के बराबर दिखा।

126 गांवों में पहली बार मतदान- नक्सल प्रभावित 126 गांवों में आजादी के बाद पहली बार लोग अपने गांव में मतदान करेंगे। हालांकि, पहुंच अभी आसान नहीं है। बताया जाता है कि ठीकठाक लोग नक्सलियों के प्रभाव में हैं।

सीआरपीएफ के 150 कैंप, अबूझमाड़ तक पहुंच- सीआरपीएफ ने अतिसंवेदनशील इलाकों में 5-5 किमी पर 150 बड़े कैंप स्थापित किए हैं। बारूदी सुरंगरोधी वाहन और हथियार लेकर एक से दूसरे कैंप तक पैदल पेट्रोलिंग करते हैं। नक्सलियों की राजधानी कहे जाने वाले नारायणपुर के अबूझमाड़ में सोनपुर तक कैंप हैं। अब इन कैंपों में ही मोबाइल टॉवर लगाए जा रहे हैं। इससे क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा मोबाइल टॉवर उड़ाए जाने जैसी घटनाएं भी घट गई हैं।

दोरनापाल से 15 किमी दूर पोलमपल्ली थाने के पुलिसकर्मियों ने बताया, कई गांवों में जाना खतरे से खाली नहीं। सहयोग मांगने पर पुलिसकर्मियों का जवाब था, अकेले जाकर लौट सकते हैं, लेकिन हमारे साथ जाने पर न लौटने की गारंटी है। जाना अपने रिस्क पर ही होगा। चिंतागुफा थाना पहुंचकर पहली बार बूथ बने करिगुंडम गांव का रास्ता पूछा तो क्या जानकारी दी गई, जैसी पोलमपल्ली में मिली थी। चिंतागुफा थाने में बताया गया कि दो दिन पहले ही वहां नक्सलियों ने एक वाहन फूंक दिया था। सलाह दी, गांव में जाना तो मोबाइल-पर्स गाड़ी में ही छोड़ देना। लेकिन स्थानीय लोगों का भरोसा जीते बगैर नक्सलियों का खात्मा मुमकिन नजर नहीं आता।

खतरे की चेतावनी- शाम के चार बजे एक गांव पहुंचे। गांव के बाहर आठ-दस ग्रामीण मिले। उनमें से एक व्यक्ति ने सवाल किया, कहां जाना है। वे चारों तरफ से ऐसे सटकर खड़े थे कि आपको एहसास भी न हो और तलाशी भी हो जाए। नशे में लग रहे थे। हमने पूछा, अब तक वोट क्यों नहीं डालते थे, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था क्या। पहले सवाल का जवाब था कि दूरी ज्यादा थी। यह पूछने पर कि अब वोट देंगे तो कहा- देखेंगे। नाम पूछने पर मुस्कुराया और कहा, इतने समय यहां बाहरी लोग नहीं आते। इसके बाद हम वहां से लौट पड़े। बातचीत कर रहे व्यक्ति छोड़ बाकी लोग थोड़ी देर बाद ही एक-एक कर निकलते रहे। पोलमपल्ली थाने में पुलिसकर्मियों ने बताया, ग्रामीणों का एक-एक कर जाना यह संकेत देता है कि गांव में नक्सली रहे होंगे।

12 सीटों पर 80 हजार जवान पहली बार महिला कमांडो भी- नक्सल क्षेत्रों की 20 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान है। इनमें से 12 बस्तर की हैं। 80 हजार जवान तैनात रहेंगे। पहली बार महिला कमांडो भी होंगी। नक्सल क्षेत्र में 100 बूथ अत्यंत संवेदनशील माने गए हैं। वहां मतदान दलों को हेलिकॉप्टर से भेजा जाएगा। मतदान दलों के वाहन जीपीएस से लैस होंगे। जिला मुख्यालयों पर बने नियंत्रण कक्ष से इनकी निगरानी होगी।

राजनांदगांव की छह और कवर्धा की दो विधानसभा सीटों पर भी पहले ही चरण में मतदान होना है। इन दो जिलों में स्थानीय पुलिस के साथ 15 हजार से अधिक जवानों को चुनाव ड्यूटी में लगाया गया है।

करीबी लड़ाई - बस्तर की 12 सीटों में से 11 (एक उपचुनाव में जीती) पर कांग्रेस का कब्जा है। 2013 के नतीजों को छोड़ दें तो कहा जाता है, बस्तर ही सरकार बनाता है। 2013 में सबसे ज्यादा 8 सीटें जीतने पर भी कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाई थी। हालांकि, लगातार सत्ता पर काबिज भाजपा को हराने की राह यहीं से खुली और 2018 में कांग्रेस ने सरकार बनाई। अब सत्ता विरोधी लहर में भी करीबी लड़ाई है। झीरम हमले में मारे गए महेंद्र कर्मा के बेटे छबींद्र कर्मा दंतेवाड़ा से कांग्रेस के टिकट पर मैदान में हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, सांसद मोहन मरकाम, कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा चर्चित चेहरे हैं। भाजपा से पूर्व मंत्री लता उसेंडी, केदार कश्यप, पूर्व आईएएस नीलकंठ टेकाम प्रमुख चेहरे हैं।

बस्तर के नक्सल प्रभावित चांदमेटा गांव में पहली बार मतदान केंद्र बनाया गया

बस्तर के अंदरूनी इलाकों में मतदान कराना चुनाव आयोग (ईसी) और सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। माओवादी संगठन हमेशा से चुनाव का बहिष्कार करता रहा है। तमाम चुनौतियों के बीच इस वर्ष अभूतपूर्व प्रगति हो रही है।

छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को होने वाला है। पहले चरण में 20 सीटों पर मतदान होगा, जिनमें से 12 सीटें बस्तर संभाग के अंतर्गत आती हैं। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में मतदान कराना चुनाव आयोग (ईसी) और सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। माओवादी संगठन हमेशा से चुनाव का बहिष्कार करता रहा है। तमाम चुनौतियों के बीच इस वर्ष अभूतपूर्व प्रगति हो रही है। प्रमंडल के 40 अंदरूनी गांवों में कुल 126 मतदान केंद्र बनाये गये हैं, जहां पहली बार मतदान होना है. पहले ये इलाके नक्सलियों के कब्जे में थे. सुरक्षा कारणों एवं जटिल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इन गांवों में मतदान केन्द्र स्थापित नहीं किये जा सके।

वैकल्पिक व्यवस्था के तहत गांव से कई किलोमीटर दूर सुरक्षित इलाकों में मतदान केंद्र बनाये गये। दूसरी ओर, नक्सलियों की ओर से ग्रामीणों को आदेश दिया गया कि जो भी वोट देगा उसकी उंगलियां काट दी जाएंगी। नतीजा यह हुआ कि ग्रामीण मतदान नहीं कर सके। लेकिन अब हालात बदल गए हैं. पिछले 4 वर्षों में बस्तर के अंदरूनी इलाकों में 60 से अधिक सुरक्षा बल कैंप स्थापित किए गए हैं। अंदरूनी इलाकों तक भी सड़कें बनाई गई हैं। नक्सलियों का क्षेत्र भी सीमित हो गया है।

मुंडागांव के बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) मदनलाल नाग ने कहा कि अभी मैं मतदाता पर्चियां बांट रहा हूं। रविवार से मैंने 638 मतदाताओं में से 512 मतदाताओं को घर-घर जाकर पर्चियां बांटी हैं। इस बार ग्रामीण अधिक जागरूक हो गए हैं। पिछले 10-15 वर्षों में। वे यह भी पूछ रहे हैं कि क्या यह लोकसभा या विधानसभा चुनाव है। इसलिए हम उन्हें बताते हैं कि विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इसलिए उनमें बहुत उत्साह है। पहले लोग वोट देने से झिझकते थे क्योंकि यह नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। पहली बार 18 साल की उम्र के सभी पुरुष और महिलाएं जो वोट देने के पात्र हैं, उन्होंने आकर अपना नाम दर्ज करवाया है और इस बार पहली बार वोट देंगे।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

नेपाल को हर संभव मदद करने के लिए भारत तैयार : मोदी

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नेपाल में

भूकंप के कारण हुए जान-माल के नुकसान पर शनिवार को दुख व्यक्त किया और कहा कि भारत अपने पड़ोसी देश के साथ एकजुटता से खड़ा है और उसे हर संभव मुहैया कराने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, 'नेपाल में भूकंप के कारण हुए जान-माल के नुकसान को लेकर बहुत दुखी हूं। भारत नेपाल के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और हर संभव मदद मुहैया कराने के लिए तैयार है। हम शोकसंतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।' पश्चिमी नेपाल के सुदूर पर्वतीय क्षेत्र में शुक्रवार आधी रात को आए 6.4 तीव्रता वाले भूकंप के तेज झटकों के कारण कम से कम 128 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। राष्ट्रीय भूकंप निगरानी एवं अनुसंधान केंद्र के अनुसार, भूकंप शुक्रवार रात को 11 बजकर 47 मिनट पर आया और इसका केंद्र जाजरकोट जिले में था।

वसुंधरा राजे ने भव्य रोड़ शो के बाद नामांकन दाखिल किया

जयपुर। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा

राजे ने आज एक भव्य रोड शो निकालने के बाद झालावाड़ सीट से भाजपा उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया। पिछले 20 सालों से राजस्थान में भाजपा की शीर्ष नेता वसुंधरा राजे को हालांकि पार्टी ने इस बार विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं घोषित किया है। उम्मीदवारों के चयन और प्रचार संबंधी कार्यों में भी वसुंधरा राजे की इस बार वह भूमिका नजर नहीं आ रही है जोकि 2003 में उनके पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद हुए पिछले सभी चुनावों में देखने को मिली थी। इस बीच, नामांकन से एक दिन पहले वसुंधरा राजे ने अपने एक बयान से दो बड़े संकेत दे दिये हैं। पहला संकेत उन्होंने यह दिया है कि वह मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल नहीं हैं, दूसरा संकेत यह है कि उन्होंने अपने सांसद बेटे दुष्यंत सिंह का नाम आगे बढ़ा दिया है।

सीएम नीतीश कुमार दिख रहे हैं परेशान

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

शनिवार सुबह-सुबह मुख्यमंत्री आवास से निकलकर सबसे पहले जदयू दफ्तर पहुंचे और वहां कुछ देर निरीक्षण करने के बाद वापस की तरफ निकल गए। इस दौरान करीब 10 मिनट तक नीतीश कुमार जदयू दफ्तर में रहे और इन चीजों की बारीकी से यह जानकारी ली कि सुबह-सुबह पार्टी दफ्तर में कौन-कौन से नेता और पदाधिकारी मौजूद रहते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री सीधे मंत्री विजय चौधरी के आवास पर पहुंचे। वहां से वह अपने आवास पहुंचे और फिर अपने प्रधान सचिव दीपक कुमार के घर पहुंच गए। मुख्यमंत्री के इस चहलकदमी का कारण तो पता नहीं चला, लेकिन कयासों का दौर शुरू हो गया है। दरअसल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए दिन सुबह-सुबह मुख्यमंत्री आवास से निकलकर सचिवालय पहुंचते हैं। वहां विभागीय पदाधिकारियों से बातचीत कर उनका फीडबैक लेते हैं।

कितने भी मोदी और शाह आ जाएं, मप्र में कांग्रेस जीतेगी

भोपाल। मध्यप्रदेश में सत्ता में वापस आने के

लिए पूरा जोर लगा रही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्य में एक रैली के दौरान बीजेपी पर ईडी, सीबीआई और आईटी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करने करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कितने भी मोदी और शाह आ जाएं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीतने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में डर पैदा करने के लिए ईडी, सीबीआई और आईटी रेड कर रही है। पीएम मोदी और भाजपा के लोग चाहते हैं कि कांग्रेस डर जाए और उनके कार्यकर्ता घर बैठ जाएं। लेकिन कितने भी मोदी और शाह आ जाएं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीतने वाली है। खड़गे ने आगे कहा, मध्य प्रदेश में भाजपा पिछले 19 साल से सत्ता में है, लेकिन फिर भी इस राज्य का विकास नहीं कर पाई। जब आप एक राज्य के हालात ठीक नहीं कर पाए, तो देश के हालात क्या ठीक करेंगे? वहीं मोदी जी करीब 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वे कांग्रेस को कोसने के अलावा और कोई काम नहीं करते।

मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तेजस्वी यादव

अहमदाबाद। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी

यादव ने शनिवार को अहमदाबाद की ट्रायल कोर्ट को सूचित किया कि मानहानि मामले को स्थानांतरित कराने की मांग को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट 6 नवंबर को मामले पर सुनवाई कर सकता है। राजद नेता ने अपने वकील के माध्यम से ट्रायल कोर्ट से मामले में पेशी से छूट देने की मांग की। अहमदाबाद की ट्रायल कोर्ट ने 22 सितंबर को तेजस्वी यादव को मानहानि मामले में समन जारी किया था। बता दें कि तेजस्वी यादव ने अपने एक बयान में कहा था कि सिर्फ गुजराती ठग हो सकते हैं। इसके विरोध में गुजरात के सामाजिक कार्यकर्ता हरेश मेहता ने तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। अब तेजस्वी यादव द्वारा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख करने पर ट्रायल कोर्ट ने मामले की सुनवाई 2 दिसंबर तक टाल दी है।

सपा अध्यक्ष ने कहा विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' पर लोकसभा चुनाव के समय चर्चा की जाएगी

गठबंधन साथियों को धोखा देने वाली पार्टी है कांग्रेस : अखिलेश

भोपाल। इंडिया गठबंधन में बिखराव का एक और अध्याय सामने आ गया है। हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच मतभेद इतने गहरा गये हैं कि इसका असर लोकसभा चुनावों में दोनों दलों के गठबंधन पर पड़ सकता है। हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांगेस पर उनकी पार्टी को 'जातिवादी और वंशवादी' बताने के लिए निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस अब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जैसी ही भाषा बोल रही है। अखिलेश यादव ने साथ ही यह भी कहा है कि यह तो अच्छा हुआ कि हमें पहले ही कांग्रेस की मंशा का पता चल गया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का इतिहास गठबंधन साथियों को धोखा देने वाले का रहा है। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी में कांग्रेस की ओर से सेंध लगाये जाने पर भी नाराजगी जताई।

हम आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए सपा का प्रचार करते हुए छतरपुर जिले के चंदला में कहा, ''यह कांग्रेस ही थी जिसने मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सपा के साथ गठबंधन करने से इंकार कर दिया।'' यादव ने कहा, कांग्रेस कहती है कि सपा 'जातिवादी और वंशवादी' पार्टी है, तो फिर उसमें और भाजपा में क्या अंतर है? वे दोनों एक ही भाषा बोलते हैं।'' अखिलेश यादव ने कहा कि वंशवादी राजनीति हर पार्टी में मौजूद है। उन्होंने कहा कि जो भी सामाजिक न्याय की बात करेगा उसे जातिवादी होने का आरोप झेलना पड़ेगा। राज्य में कांग्रेस द्वारा सपा उम्मीदवारों की खरीद-फरोख्त पर यादव ने कहा, ''यह उनके इरादों को दर्शाता है...उन्हें ऐसा करने दीजिए। मध्य प्रदेश के लोगों ने देखा है कि यह कांग्रेस ही थी जिसने गठबंधन को खारिज कर दिया था। हम आपको बता दें कि अखिलेश यादव चंदला में पार्टी प्रत्याशी पुष्पेंद्र अहिरवार के समर्थन में एक आमसभा को संबोधित करने आये थे।

जनसभा को संबोधित करते हुए यादव ने कहा कि कुछ दल सपा को जातिवादी कह रहे हैं, लेकिन समाजवादी कभी भी जातिवादी नहीं हो सकते क्योंकि वे सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि जब भी सपा सत्ता में आएगी या उसके समर्थन से राज्य में सरकार बनेगी, तो सबसे पहले जातीय जनगणना कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि चंदला की जनता ने दो बार सपा प्रत्याशियों को आशीर्वाद दिया है और इस बार भी वह उसकी जीत सुनिश्चित करेगी।

बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के बारे में सपा प्रमुख यादव ने कहा कि इस पर लोकसभा चुनाव के समय चर्चा की जाएगी, क्योंकि केवल पीडीए (पिछड़ा, दलित और आदिवासी) की ताकत ही भाजपा को हरा सकेगी। उन्होंने एक प्रश्न पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कमलनाथ बुजुर्ग हैं, लेकिन सत्तारुढ़ भाजपा के पास मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या से अधिक मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। चुनाव के बाद किसी पार्टी को समर्थन देने पर यादव ने कहा कि वह केवल उसी पार्टी को समर्थन देने पर विचार करेंगे जो जातीय जनगणना कराएगी। हालाँकि, यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान पर टिप्पणी करने से परहेज किया कि विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन में कुछ भी नहीं हो रहा है, उन्होंने कहा कि वह इस बारे में बाद में बात करेंगे। सपा प्रमुख यादव ने कहा, ''भाजपा भी अब पिछड़े वर्गों को अधिक टिकट देने की बात कर रही है। यह मानसिकता में बड़े बदलाव को दर्शाता है। यहां तक कि कांग्रेस, जिसने आजादी के बाद जातीय जनगणना कराना बंद कर दिया था, अब इसके बारे में बात कर रही है...इसका मतलब है कि उन्हें पीडीए की ताकत का एहसास हो रहा है।'' दलित या पिछड़े वर्ग के किसी सदस्य को मुख्यमंत्री बनाने के चुनावी वादे के बारे में पूछे जाने पर यादव ने दावा किया कि कांग्रेस और भाजपा दोनों कभी भी दलितों और पिछड़े वर्गों के पक्ष में निर्णय नहीं लेंगी।

नीतीश को खड़गे ने किया फोन

नईदिल्ली। बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू नेता नीतीश कुमार ने इंडिया ब्लॉक के कमजोर होने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था। अब कांग्रेस नीतीश कुमार को मनाने में लग गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनसे फोन पर बात की और उन्हें बताया कि विपक्षी गठबंधन उनकी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस अभी पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों पर ध्यान केंद्रित कर रही है और राज्य चुनाव खत्म होने के बाद इंडिया ब्लॉक के एजेंडे और संयुक्त रैलियों पर ध्यान केंद्रित करेगी। सूत्रों के मुताबिक, मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार से कहा कि कांग्रेस तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में विधानसभा चुनावों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जहां पार्टी का बड़ा दांव है। 2 नवंबर को नीतीश कुमार ने गुरुवार को पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की व्यस्तता को हाल के महीनों में हासिल की गई गति को आगे बढ़ाने में भारतीय ब्लॉक की असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया।

स्मृति ईरानी के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार

भाजपा कर रही है बदले की राजनीति : कांग्रेस

नईदिल्ली। महादेव बेटिंग ऐप घोटाले को लेकर भाजपा ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि सत्ता में रहकर, सट्टा का खेल छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेतृत्व का एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुका है। शुक्रवार को भूपेश बघेल के खिलाफ कुछ चौंका देने वाले तथ्य देश के सामने प्रस्तुत हुए हैं। असीम दास नामक एक व्यक्ति से 5.30 करोड़ रुपए से ज्यादा बरामद हुए हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि मैं आज कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूं- क्या ये सत्य है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेताओं को शुभम सोनी के माध्यम से असीम दास पैसा पहुंचाते थे? क्या ये सत्य है कि शुभम सोनी के एक वॉइस मैसेज के माध्यम से असीम दास को ये आदेश दिया गया कि वो रायपुर जाएं और भूपेश बघेल को चुनाव के खर्चे के लिए पैसा दें? केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हवाला ऑपरेटरों का इस्तेमाल कर छत्तीसगढ़ का चुनाव लड़ रही है। छत्तीसगढ़ पुलिस और आंध्र प्रदेश बीजेपी के प्रशासनिक दायरे में नहीं आते हैं. तो क्या भूपेश बघेल अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं?

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को संकटग्रस्त महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटरों से 508 करोड़ मिलने के प्रवर्तन निदेशालय के दावे के एक दिन बाद बघेल ने इसका दृढ़ता से खंडन किया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पूछा कि क्या बघेल अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। महादेव ऐप चर्चा में है क्योंकि हाल ही में दुबई स्थित इस प्लेटफॉर्म के संबंध में कई बॉलीवुड हस्तियों से पूछताछ की गई थी। ईडी ने कहा कि उसने एक वेब बेनामी बैंक खाते और राज्य में चुनाव के लिए कुछ बघेलों को दिए गए 508 करोड़ के फंड से जुड़े एक कबूलनामे का खुलासा किया। बघले ने आरोप पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि क्या इससे बड़ा मजाक हो सकता है? अगर आज मैं किसी को पकड़ लूं और उससे पीएम मोदी का नाम लेने के लिए कहूं,

तो क्या वे (ईडी) उससे पूछताछ करेंगे? किसी की प्रतिष्ठा को धूमिल करना बहुत आसान हो गया है।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने स्मृति इरानी की शनिवार सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जैसे ही बीजेपी सुबह-सुबह ईडी के बचाव में खुलकर सामने आई, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में ईडी और बीजेपी के बीच मिलीभगत साबित हो गई। बता दें कि बीजेपी की तरफ से पूरे मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। स्मृति ईरानी ने कहा कि छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में महादेव ऐप के संबंध में एफआईआर दर्ज की गई थीं। दोनों राज्यों में, भाजपा सत्ता में नहीं है। तो फिर भूपेश बघेल के खिलाफ साजिश कौन कर रहा है? स्मृति ईरानी ने कहा कि यह मामला हाल का नहीं है।

एफआईआर 2022 में दर्ज की गई थी और तब से जांच चल रही है। कांग्रेस हवाला ऑपरेटरों के जरिए चुनाव लड़ रही है। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव ने कहा कि अगर स्मृति ईरानी के पास सबूत थे तो उन्हें सबके सामने पेश करना चाहिए था। वह आरोप क्यों लगा रही है? अगर उसके पास जानकारी है लेकिन वह इसे प्रकाश में नहीं ला रही है, तो क्या वह भी इसमें एक पक्ष है? यह वही ईडी है जिसके अधिकारियों के घरों में भारी मात्रा में पैसा है। हम थे उम्मीद है कि चुनाव से ठीक पहले ऐसा होगा। यह अप्रत्याशित नहीं है। जब वे चुनाव हारने वाले हैं, तो वे ये बातें सामने ला रहे हैं।

खेल
प्रमुख समाचार

आज भारत के सामने दक्षिण अफ्रीका की कठिन चुनौती

कोलकाता। लगातार सात जीत के साथ

आत्मविश्वास से लबरेज भारतीय टीम को इस वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका के रूप में पहली कठिन चुनौती मिलने जा रही है और शीर्ष दो टीमों के बीच रविवार को 'फाइनल से पहले फाइनल ' माने जा रहे इस मुकाबले में 'बर्थडे ब्वॉय' विराट कोहली पर सभी की नजरें होंगी।

करीब 65000 की दर्शक क्षमता वाले ऐतिहासिक ईडन गार्डंस पर होने वाला यह मैच भारत के लिये इस टूर्नामेंट की सबसे कठिन चुनौती है चूंकि नीदरलैंड के खिलाफ एक मैच को छोड़कर दक्षिण अफ्रीका ने छह मुकाबले जीते हैं। लेकिन भारत ने अभी तक एक चैम्पियन की तरह खेल दिखाया है और सेमीफाइनल में प्रवेश के बाद अंतिम दोनों लीग मैच में बड़ी जीत दर्ज करके उसके इरादे नंबर एक पर बने रहने के होंगे। बल्लेबाजी में मेजबान के लिये सर्वाधिक 442 रन बना चुके कोहली वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी की कोशिश में होंगे। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो उसने पुणे में पिछले मैच में न्यूजीलैंड को 190 रन से हराया और अब सेमीफाइनल में पहुंचने के लिये बस एक जीत की जरूरत है। दक्षिण अफ्रीका के 12 अंक है और प्लस 2.290 का शानदार रनरेट भी है लिहाजा यहां हारने पर भी उसका अंतिम चार में रहना तय है। अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे क्विंटोन डिकॉक (545 रन) का फॉर्म गेंदबाजों के लिये दुस्वप्न साबित हो रहा है। दक्षिण अफ्रीका टीम पांच बार 300 से ऊपर का स्कोर बना चुकी है जिसमें एडेन मार्कराम (सात पारियों में 362 रन), रासी वान डेर डुसेन (सात पारियों में 353 रन) और हेनरिच क्लासेन (315 रन) का भी अहम योगदान रहा है। अब देखना यह होगा कि भारतीय तेज तिकड़ी दक्षिण अफ्रीका के लिये रन उगलते इन बल्लेबाजों के बल्लों की धार कैसे कुंद कर पाती है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

इंटेल ने 8 ईएमएस कंपनियों से लैपटॉप बनाने मिलाया हाथ

नईदिल्ली। ग्लोबल सेमीकंडक्टर मेकर इंटेल ने 'मेक इन इंडिया' लैपटॉप बनाने के लिए शुक्रवार को आठ भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनियों और मूल डिजाइन निर्माताओं के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की। इंटेल भारत में अपने लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्टस के लिए इन कंपनियों के साथ प्रमुख तकनीकी और ऑपरेशन इनसाइट साझा कर रहे हैं। नए सहयोग के हिस्से के रूप में, इंटेल ने भारत में एंट्री लेबल के लैपटॉप के उत्पादन में अपनी विशेषज्ञता साझा की है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया, ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स, कायन्स टेक्नोलॉजी इंडिया, भगवती प्रोडक्ट्स, पैनाचे डिजीलाइफ, स्माइल इलेक्ट्रॉनिक्स, सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी और वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज इंटेल द्वारा डिजाइन की गई लैपटॉप निर्माण प्रक्रियाओं का उपयोग करने में सक्षम हो सकते हैं।

एसबीआई का दूसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट 9.13% बढ़ा

नईदिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही का एकीकृत नेट प्रॉफिट 9.13 प्रतिशत वृद्धि के साथ 16,099.58 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने शनिवार को यह जानकारी दी। बैंक ने पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 14,752 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध लाभ दर्ज किया था। बैंक ने बताया कि एकल आधार पर उसका शुद्ध लाभ समीक्षाधीन तिमाही में 14,330.02 करोड़ रुपये रहा है जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 13,264.52 करोड़ रुपये रहा था। आलोच्य तिमाही में बैंक की कुल आमदनी 1.12 लाख करोड़ रुपये रही जो सितंबर, 2022 तिमाही में 88,733 करोड़ रुपये रही थी। एसबीआई के पास कुल बाजार का पांचवां हिस्सा है और देश में इसका सबसे बड़ा नेटवर्क है।

वायु गुणवत्ता खराब होने पर बढ़ी एयर प्यूरीफायर की बिक्री

नईदिल्ली। इन दिनों भारत की राजधानी दिल्ली और उसके आस पास के इलाकों में वायु गुणवत्ता काफी खराब स्थिति में पहुंची हुई है। शनिवार की सुबह 7 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 416 दर्ज हुआ है, जो कि शुक्रवार को 460 पर पहुंचा हुआ था। 416 के स्तर पर भी वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। ऐसा ही हाल दिल्ली के आसपास एनसीआर इलाके का भी है। वहीं खराब वायु गुणवत्ता को देखते हुए अब एयर प्यूरीफायर की बिक्री में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इन दिनों वायु प्रदूषण बढ़ने से एयर प्यूरीफायर की बिक्री में इजाफा हुआ है। दिल्ली और एनसीआर में लगातार खराब वायु प्रदूषण को देखते हुए अब एयर प्यूरीफायर के संबंध में दुकानदारों से ग्राहक काफी अधिक पूछताछ कर रहे है। कंपनी निर्माताओं का कहना है कि उन्हें नयी दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के साथ ही मुंबई और देश के कुछ पूर्वी हिस्सों से पूछताछ मिल रही है।

बफर स्टॉक से एक लाख टन प्याज बेचेगी केंद्र सरकार

नई दिल्ली। त्योहारी सीजन में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर में खुदरा बाजारों में अपने बफर स्टॉक से एक लाख टन प्याज जारी करने की घोषणा की है। इसी के तहत शुक्रवार को 100 से अधिक शहरों के लिए प्याज जारी कर दी गई। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार ने कहा, सरकारी हस्तक्षेप के कारण कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, इंदौर, भोपाल, रायपुर, रांची, जयपुर और कोटासहित कई शहरों में प्याज की कीमत कम हो गई है। दिल्ली व आसपास के इलाकों में प्याज 70 से 80 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) ने शुक्रवार को कहा, वह दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के अलावा जम्मू-कश्मीर से लेकर केरल तक सभी राज्यों में 25 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती भाव पर प्याज बेचेगा।

सफलता के सातवें आसमान पर टीम इंडिया

अनुराग भारती

बदली विरोधी टीम.. बदला मैदान.. लेकिन वही अंजाम। सात में से सात और सातवें आसमान पर टीम इंडिया। अंक तालिका में टॉप पर टीम इंडिया और सेमीफाइनल का टिकट पक्का। वनडे क्रिकेट विश्व कप में विजय रथ पर सवार रोहित शर्मा एंड टीम ने श्रीलंका के खिलाफ जीत का सत्ता इस अंदाज में लगाया मानों विरोधी टीमों से कह रहे हों- यहां के हम सिकंदर।

टीम इंडिया का हर खिलाड़ी मैदान पर बल्ले और गेंद से एकदम फिट और सुपरहिट। पाकिस्तान हो या फिर श्रीलंका, भारतीय खिलाड़ी घरेलू मैदानों पर जिस अंदाज में अपने प्रदर्शन से आग उगल रहे हैं, वो बताता है कि अगर क्रिकेट महाकुंभ में ये सिलसिला आगे भी जारी रहा तो बादशाहत अब दूर नहीं। वानखेड़े स्टेडियम में कल जिस तरह से टीम इंडिया ने श्रीलंका के परखचे उड़ाये हैं उससे आहट सुनाई देने लगी है कि वनडे क्रिकेट का बादशाह अब बदलने वाला है। 12 साल बाद बादशाहत का ताज भारत के सिर सजने की करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें बल्लियों उछलने लगी हैं।

वैसे क्रिकेट की दुनिया थोड़ी अलग है... अनिश्चितताओं से भरी हुई है... यहां कुछ भी तय नहीं है.. कोई कभी अर्श पर तो कभी फर्श पर। साल दर साल क्रिकेट की दुनिया की बादशाहत का बैटन भी एक देश से दूसरे देश के हाथों में जाता दिखा। मिसाल के तौर पर मौजूदा वनडे विश्व कप को ही देख लीजिए। चार साल पहले इंग्लैंड 50 ओवर के क्रिकेट महाकुंभ में अपने घरेलू मैदानों पर न्यूजीलैंड को हरा कर पहली बार चैंपियन बना। चार साल बाद भी उसे खिताब जीतने की दौड़ में फेवरिट आंका जा रहा था, लेकिन मैदान पर जो तस्वीरें अब तक दिखीं, उस पर

किसी को यकीन ही नहीं हो रहा है। तस्वीर 360 डिग्री उलट चुकी है। भारतीय मैदानों पर मौजूदा चैंपियन चारों खाने चित दिख रहा है।

वनडे विश्व कप टूर्नामेंट में एक दूसरे से जोर आजमाइश कर रही 10 टीमों के बीच अंक तालिका में इंग्लैंड आखिरी पायदान पर है। टूर्नामेंट में अब तक खेले छह मैचों में से इंग्लैंड को पांच में हार का सामना करना पड़ा है। उसे जो इकलौती जीत मिली, वो भी बांग्लादेश जैसी कमजोर टीम के खिलाफ। इंग्लैंड के खिलाड़ी और फैन परेशान और दुनिया हैरान है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि क्रिकेट का जन्मदाता देश कमजोर समझी जाने वाली आयरलैंड, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसी टीम से भी फिसड्डी साबित हो रही हैं। अब न सिर्फ मौजूदा विश्व कप से इंग्लैंड की विदाई करीब करीब तय है बल्कि उसके 2025 चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है। इंग्लैंड पर तलवार इसलिए लटक रही है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में कुल आठ टीमें मैदान पर जोर आजमाइश करेंगी। इनमें से सात टॉप टीमें होंगी जबकि आठवीं टीम मेजबान पाकिस्तान की होगी। वैसे 146 साल पुरानी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की दुनिया में बड़ी-बड़ी टीमों की बादशाहत के यों चकनाचूर होने की ये कहानी नई नहीं है। 19वीं सदी में इंग्लैंड के मैदानों से शुरू हुई गेंद और बल्ले की इस जंग की कहानी साल दर बदलती रही और आगे बढ़ती रही।ये वो दौर था जब दुनिया भर में फैले ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में कहा जाता था कि उसका सूरज कभी नहीं डूबता। जिस देश में अंग्रेज गए, वहां के लोगों को उन्होंने क्रिकेट के खेल का सबक सिखा ही दिया। भारत से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक और कैरिबियाई द्वीपों से ऑस्ट्रेलिया तक जल्द ही क्रिकेट अपनी पैठ बना चुका था। इंग्लैंड में खेल अलग-अलग फॉर्मेट में परवान भी चढ़ा लेकिन इंग्लैंड की टीम अपने ही बनाए खेल में ही पिछड़ती दिखी और वनडे क्रिकेट में तो बादशाह का तमगा हासिल करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। वैसे एक दौर ऐसा आया जब क्रिकेट की दुनिया में सिर्फ एक ही टीम की तूती बोलती थी। ये थी वेस्टइंडीज की टीम। तेज गेंदबाजी में ऐसी खौफनाक धार कि उसके सामने बड़े से बड़े बल्लेबाज की टांगें कांपने लगती थीं। 1970 के दशक में फैब फोर के नाम से मशहूर एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, जोएल गार्नर और मैलकॉम मार्शल की पेस चौकड़ी ने मैच दर मैच मैदान पर नई इबारतें लिखीं।

छत्तीसगढ़ में चुनावी बाजी पलटने में लगी भाजपा

भाजपा ने 2023 के चुनाव में स्लोगन दिया है अउ नइ सहिबो, बदल के रहिबो.....। छत्तीसगढ़ में सत्ता में आने के लिए भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में वादों का अंबार लगा दिया है। किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और कर्मचारियों के लिए वादे किए हैं। 2018 में किसानों से दूर भागने वाली भाजपा इस बार उन पर मेहरबान दिख रही है। कांग्रेस ने अभी अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, लेकिन उसके नेता अलग -अलग सभाओं में किसानों, महिलाओं, युवाओं और मजदूरों के लिए कई घोषणाएं कर चुके हैं। कांग्रेस बिना घोषणा पत्र के ही करीब 17 घोषणाएं कर चुकी है। लोगों को कांग्रेस के घोषणापत्र का इंतजार है। छत्तीसगढ़ में किसान और धान बड़ा चुनावी मुद्दा है। 2018 चुनाव में ये दो मुद्दे बड़े असरकारक रहे। घोषणाओं के कारण छत्तीसगढ़ का चुनावी माहौल गर्म हो गया है। दोनों बड़ी पार्टियों की घोषणाओं के कारण अब मतदाताओं के सामने विकल्प पैदा हो गया है। भाजपा के संकल्प पत्र से लोगों को अहसास हो रहा है कि वह 2023 में हर हाल में छत्तीसगढ़ की सत्ता चाहती है। संकल्प पत्र के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 नवंबर को दुर्ग की सभा में गरीब परिवारों के लिए अगले पांच साल तक मुफ्त अनाज योजना जारी रखने की घोषणा कर गए।

कही-सुनी

रवि भोई

अरुण साव से ज्यादा वीवीआईपी अमित जोगी

कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की नजर में इन दिनों भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की तुलना में ज्यादा वीवीआईपी जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी हो गए हैं। केंद्र सरकार ने अमित जोगी को सीआरपीएफ का प्रोटेक्शन तो दिया ही है , उनके निवास को भी सीआरपीएफ की छावनी में तब्दील कर दिया है। अमित जोगी के प्रति केंद्र सरकार के प्यार को 2023 के चुनावी गणित से जोड़कर देखा जा रहा है। कहते हैं भाजपा ने अरुण साव की सुरक्षा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को 3 -4 बार पत्र भी लिखा, लेकिन अरुण साव की सुरक्षा बढ़ाने में न राज्य सरकार ने दिलचस्पी ली और न ही केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने अमित जोगी को जरूर वीवीआईपी बना दिया। अमित जोगी पाटन विधानसभा से प्रत्याशी हैं, जहाँ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उम्मीदवार हैं। जोगी कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में 81 प्रत्याशी खड़े किए हैं।

संकल्प पत्र को लेकर भाजपा नेताओं में मनभेद

कहते हैं कि संकल्प पत्र में तेंदूपत्ता के भारीभरकम रेट निर्धारण और फड़ मुंशियों को एकमुश्त राशि देने के मामले में भाजपा के स्थानीय और दिल्ली के नेताओं में भारी मनभेद रहा। खबर है कि तेंदूपत्ता का रेट 5500 रुपए मानक बोरा करने के मामले में राज्य के नेता सहमत नहीं थे, उनका मानना था कि राजकोष पर भारी बोझ पड़ेगा। कहा जा रहा है कि दिल्ली के नेताओं ने राज्य के नेताओं की बात अनसुनी कर दी और फैसला कर लिया। अब संकल्प पत्र सार्वजनिक होने के बाद भाजपा के राज्य के नेताओं के पसीने छूटने लगे हैं। वे मानकर चल रहे हैं कि सरकार बनी तो फंड की व्यवस्था उन्हें ही करनी पड़ेगी।

सरकार बनाए नहीं, पर बनवाएंगे

कहते हैं जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है, वहां के नेता छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनवाने आए हैं। खबर है कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनवाने के लिए पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और ओडिशा के नेता आए हैं। इन राज्यों में अभी भाजपा की सरकार नहीं है। पश्चिम बंगाल में तो भाजपा नेताओं ने सरकार का सुख ही नहीं भोगा है, बाकि राज्यों में मिलीजुली सरकार में रह चुके हैं। इन राज्यों से आए नेता ही चुनावी कमान संभाले हुए हैं। इससे स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बिस्तर पकड़ना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है बात बिगड़ते देख अब गुजरात के नेताओं का एक दल छत्तीसगढ़ पहुँच गया है।

भाजपा प्रत्याशी का जख्म हुआ ताजा

भाजपा ने एक रिजर्व सीट पर एक डाक्टर को प्रत्याशी बनाया है। अब चुनाव के वक्त डाक्टर का पुराना जख्म ताजा हो गया है। कहते हैं डाक्टर रायपुर के निवासी हैं। जुगाड़ से टिकट मिल गई। हेलीकाप्टर प्रत्याशी होने के कारण पहले जमीनी नेता और कार्यकर्ता नाराज हुए और बवाल मचाया। अब जनता डाक्टर के पुराने घाव को कुरेदने लगी है। कहते हैं डाक्टर कुछ साल पहले किडनी कांड में बाल-बाल बचे थे। डाक्टर चुनाव मैदान में उतरे तो उनके दुश्मनों ने पुराना मामला निकाल लिया है। अब भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपने प्रत्याशी के बारे में लेने के देने पड़ गए। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है।

रेत में फंस गई कांग्रेस की विधायक

कहते हैं कांग्रेस की एक विधायक रेत के फेर में फंसकर टिकट गवां बैठी। खबर है कि पहली बार की कांग्रेस विधायक ने अपने कुछ लोगों के नाम पर रेत खदान ठेके पर ले लिया था और पूरे पांच साल अपने क्षेत्र में उन्हीं लोगों को साथ लेकर घूमती भी रही। इससे क्षेत्र के कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भारी गुस्से में थे। जब विधायक को टिकट देने के बारे में पूछताछ और रायशुमारी चली तो विधायक की मौजूदगी में कांग्रेस के बड़े नेताओं के सामने क्षेत्र के कांग्रेस नेता फूट पड़े। कहा जा रहा है कि क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं के तेवर देखकर हाईकमान ने विधायक को अगला मौका देना मुनासिब नहीं समझा। रेत खदान के चक्कर में विधायक अपने क्षेत्र में पदस्थ अफसर से सार्वजनिक तौर पर लड़ पड़ीं थीं।

चुनावी शबाब के बीच ईडी का खेला

वैसे तो ईडी पिछले कई महीनों से छत्तीसगढ़ में आपरेशन को अंजाम दे रही है। वह कोयला, शराब, खनिज, चावल से लेकर महादेव ऐप आन सट्टा को लेकर ब ड. ी - ब ड. ी कार्रवाई कर चुकी है। ईडी की कार्रवाई के कारण राज्य के कई अफसर और कारोबारी जेल में बंद हैं, लेकिन विगत तीन नवंबर की कार्रवाई राज्य की राजनीति को हिला देने वाली रही। राज्य में विधानसभा चुनाव शबाब पर है, ऐसे में ईडी के प्रेस नोट में कांग्रेस के बड़े नेता के नाम का उल्लेख करते हुए चुनाव में इस्तेमाल के लिए यूएई से पैसा आने की बात कर बड़ा विस्फोट कर दिया है। इस धमाके की गूंज जबरदस्त हुई है। ईडी ने कूरियर को गिरफ्तार कर लिया है। कहते हैं हैं कूरियर से ईडी ने बहुत कुछ उगलवा लिया है। चलते चुनाव में ईडी की बड़ी कार्रवाई का अंदेशा पहले से ही लोगों को था। शुक्रवार की घटना से संभावना सच में बदल गया।

खाल बचाने के लिए बिजली अफसर की जुगत

कुछ लोगों की आदत होती है,अपनी गलती का ठीकरा दूसरों के ऊपर फोड़ना। ऐसा ही कुछ डंगनिया में ऊंची कुर्सी पर बैठे एक अफसर कर रहे हैं। कहते हैं हवा-पानी में टूटे बिजली खंभों की मरम्मत के लिए बिना आंकलन के इस अफसर ने खुद ही कमीशन के फेर में 10 करोड़ का फंड रिलीज कर दिया। कहा जा रहा है कि कायदे से संभाग स्तर से प्रस्ताव बुलवाना चाहिए था। अब अफसर की कलम फंस गई और गड़बड़ी सतह पर दिखाई देने लगी तो इस अफसर ने गलती का ठीकरा संभाग पर फोड़ दिया और जांच का फरमान दे दिया। इस अफसर ने अपने गले में फंदा डलते देख अपने कुछ मातहतों को बलि का बकरा भी बना दिया। बिजली मुख्यालय में बैठे अफसर की करतूत की जानकारी उनसे ऊँचे अफसरों को नहीं लगी है,क्योंकि वे अभी कुम्भकर्णी नींद में हैं। अब देखते हैं गलती कर कितने दिन तक ये अफसर अपनी खाल बचाते फिरते हैं।

(लेखक पत्रिका समवेत सृजन के प्रबंध संपादक और स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

नक्सलियों के साथ हर अपराधी को उल्टा लटकाकर लेंगे हिसाबः डॉ. रमन सिंह

रायपुर. चुनाव से पहले नारायणपुर में नक्सलियों ने भाजपा नेता को मौत के घाट उतार दिया है. वहीं इस घटना को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला है. साथ ही भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने भी ट्वीट कर घटना की निंदा की है. रमन सिंह ने ट्वीट कर लिखा, नारायणपुर में भाजपा के हमारे जिला उपाध्यक्ष और कौशलनार क्षेत्र से जनपद सदस्य रतन दुबे जी की हत्या का दुखद समाचार प्राप्त हुआ. ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति तथा शोकाकुल परिजनों को धैर्य व संबल प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं.

आगे रमन सिंह ने लिखा, विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने और भाजपा को डराने के उद्देश्य से लगातार हमारे साथियों की टारगेट किलिंग करवाने वाली कांग्रेस यह समझ ले कि भाजपा डरने वाली नहीं है, छत्तीसगढ़ की जनता हमारे साथ है. बहुत जल्द नक्सलियों के साथ ही हर अपराधी को उल्टा लटकाकर हिसाब लिया जाएगा.

भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के नारायणपुर विधानसभा के संयोजक व ज़िला उपाध्यक्ष रतन दुबे जी की प्रचार के दौरान नक्सलियों द्वारा निर्ममता से की गयी हत्या से मैं बेहद व्यथित हूँ, इस कायरत्तापूर्ण घटना की समूची पार्टी निंदा करती है.

क्या कांग्रेस नेताओं को पैसे देता था असीम दास? भूपेश बघेल से स्मृति ईरानी ने पूछे सवाल

रायपुर। महादेव बेटिंग ऐप घोटाले को लेकर भाजपा ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हमला बोला है। केंद्रिय मंत्री स्मृति ईरानी ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि सत्ता में रहकर, सट्टा का खेल छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेतृत्व का एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुका है। कल भूपेश बघेल जी के खिलाफ कुछ चौंका देने वाले तथ्य देश के सामने प्रस्तुत हुए हैं। असीम दास नामक एक व्यक्ति से 5.30 करोड़ रुपए से ज्यादा बरामद हुए हैं।

स्मृति ईरानी ने कहा कि मैं आज कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूं- क्या ये सत्य है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेताओं को शुभम सोनी के माध्यम से असीम दास पैसा पहुंचाते थे? क्या ये सत्य है कि शुभम सोनी के एक वॉइस मैसेज के माध्यम से असीम

दास को ये आदेश दिया गया कि वो रायपुर जाएं और भूपेश बघेल को चुनाव के खर्चे के लिए पैसा दें?

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हवाला ऑपरेटरों का इस्तेमाल कर छत्तीसगढ़ का चुनाव लड़ रही है. छत्तीसगढ़ पुलिस और आंध्र प्रदेश बीजेपी के प्रशासनिक दायरे में नहीं आते हैं. तो क्या भूपेश बघेल अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं?

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को महादेव ऐप प्रमोटर्स द्वारा 508 करोड़ रुपये का भुगतान करने के ईडी के दावे पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। कांग्रेस की आदत है भ्रष्टाचार करना और सत्ता में आना। भूपेश बघेल का खेल बंद हो जाएगा और उन्हें जेल जाना पड़ेगा।

ईडी ने किया ये दावा

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को दावा किया कि महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी एप के प्रमोटरों ने सीएम बघेल को 508 करोड़ रुपये दिए हैं। ईडी ने कहा कि 5.39 करोड़ रुपये के साथ गिरफ्तार किए गए असीम दास ने पूछताछ में सीएम को पैसा दिए जाने की बात कही है। एजेंसी ने यह भी कहा है कि सीएम के खिलाफ जो भी आरोप लगे हैं वे जांच का विषय हैं।

आराम से बन रही भाजपा की सरकारः बाबूलाल मरांडी

रायपुर। झारखंड के पूर्व सीएम और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश में भाजपा के पक्ष में माहौल होने की बात कही है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी आराम से सरकार बना रहा है. कोंडागांव विधानसभा में प्रचार के लिए पहुंचे बाबूलाल मरांडी ने मीडिया से चर्चा में कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष लाल भाई जी देसाई के 'रंगा-बिल्ला' वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश को वर्षों तक लूटा, इसलिए लूट ही दिखता है. मोदी जी ने जब से कहा है कि न खाऊंगा, न खाने दूंगा. तब से सबका पसीना छूट रहा है. राहुल गांधी को लेकर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वो कुछ भी बोलते रहता है, इसलिए कांग्रेस का इस बार सूपड़ा साफ है. राहुल गांधी के दौरे पर कहा कि राहुल गांधी दौरा नहीं, पिकनिक करते हैं. राहुल गांधी को देश की जनता ने 2014 में रिजेक्ट कर दिया था.

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

वर्तमान सरकार से नहीं खुश है जनता, भाजपा से फिर उम्मीदः नितिन नबीन

अम्बिकापुर। छत्तीसगढ़ भाजपा के सह प्रभारी नितिन नबीन एवं पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम, भाजपा राष्ट्रीय मंत्री डॉ आशा लकड़ा, संभागीय चुनाव प्रभारी विधायक अनंत ओझा तथा भाजपा जिलाध्यक्ष ललन प्रताप सिंह की उपस्थिति में अलग से सरगुजा के लिए घोषणा पत्र जारी किया गया। घोषणा पत्र जारी उपरांत होटल परपल ओरचीड, अंबिकापुर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ सह-प्रभारी नितिन नबीन सहित पूर्व सांसद राम विचार नेताम ने कहा कि वर्तमान सरकार को लेकर लोगों में आक्रोश है, जनता को फिर से भाजपा से उम्मीद है। सरगुजा की दृष्टिकोण से अलग घोषणा पत्र लाया गया है जिसे लेकर उन्होंने कहा कि तेंदूपत्ता संग्रहण दर एवं बोनस देंगे। तेंदूपत्ता का संग्रहण 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा में करेंगे। संग्रहण मौजूदा दिनों से बढ़ाकर 15 दिनों तक किया जाएगा। इसके अतरिक्त संग्राहकों को 4,500 रुपये तक बोनस दिया जाएगा। चरणपादुका एवं अन्य सुविधाएं पुनः प्रदान की जाएगी।राज्य के प्रत्येक जनजातीय परिवार को आजीविका में बढ़ोतरी हेतु 2 बकरियाँ देने की बात कही। इसके अलावा हर्रा, साल बीज, इमली, इमली बीज और इमली के फूल का संग्रहण दर बढ़ाएंगे।

मोदी किसान के नहीं अडानी के मितान हैः ठाकुर

रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि किसान विरोधी पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह मोदी की चाटुकारिता में किसान विरोधी मोदी को किसानों का मितान बताकर मितान जैसे पवित्र रिश्ता को अपमानित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मितान एक ऐसा रिश्ता है जो एक दूसरे के सुख और दुख में मजबूती के साथ खड़ा होता है और मोदी तो हमेशा किसानों के विरोध में काम किये हैं। असल में मोदी किसानों के नहीं बल्कि अडानी के मितान है क्योंकि प्रधानमंत्री की पद की शपथ लेने के बाद मोदी ने सिर्फ अडानी के हित में काम किया है।मोदी अगर किसानों के मितान होते तो दिल्ली की सीमा में किसान 14 महीना तक भरी गर्मी, तेज बारिश, कड़ाके के ठंड में खेत खलिहान घर द्वार बचाने आंदोलन नही करते, 800 से अधिक किसानों को अपनी जान गवानी नही पड़ती। मोदी अडानी की मित्रता देश ही नही पूरी दुनिया मे चर्चित है कि कैसे अडानी के फायदे के लिये भाजपा की केंद्र राज्य की सरकार लगी है। अडानी के हित में ही तो तीन काला कृषि कानून लाया गया था और किसानों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र रचा गया था प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के किसान विरोधी चरित्र को छत्तीसगढ़ के किसान पहचानते है। ये वही रमन सिंह है जिन्होंने किसानों को धान की कीमत 2100 रु. प्रति क्विंटल और 300 रु. बोनस नहीं दिया।

तरक्की की राह पर जाएगा प्रदेश :कौशिक

बिलासपुर। बिलासपुर की बिल्हा सीट से भाजपा प्रत्याशी धरमलाल कौशिक ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी किये घोषणा पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार मानते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी वर्गों की चिंता करते हुए यह घोषणा पत्र जारी किया गया है। जिसमें किसानों, महिलाओं, विद्यार्थियों, युवाओं, अधिकारी- कर्मचारियों, बुजुर्गों, शिक्षकों, एसटी, एस सी व पिछड़ा वर्ग जैसे सभी वर्गों की चिंता की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में पांच सालों तक शासन किया किन्तु उन्होंने केवल सत्ता पाने के लिये झूठे घोषणा पत्र जारी किया था जिससे छत्तीसगढ़ के सभी जनता का भरोसा टूट चुका है किन्तु इस घोषणा पत्र से जनता का जो भरोसा टूटा था, विश्वास टूटा था वह अब पुनः वापस आएगा। धरमलाल कौशिक ने कहा कि यह घोषणा पत्र पुरी तरह से छत्तीसगढ़ के विकास और विश्वास का घोषणा पत्र है। छत्तीसगढ़ के नागरिकों की विकासात्मक आकांक्षाओं को समझकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के नागरिकों से घोषणा पत्र के रूप में अपनी गारंटी दी है। इस गारंटी के दम पर हम पुनः छत्तीसगढ़ को तरक्की की राह पर आगे ले कर जाएंगे। भाजपा प्रत्याशी कौशिक ने कहा कि भाजपा का रिकॉर्ड है कि हमारा चुनाव घोषणा पत्र सिर्फ घोषणा मात्र नहीं बल्कि हमारे लिए ये संकल्प पत्र होता है।

नागरिकों से मतदान करने की हुई अपील, कहा हैप्पी वोटिंग

रायपुर । सिक्स सिक्स सिक्स कैच पकड़ो, छूटने ना पाए, आउट, अब हैट्रिक मिलेगा ऐसी जोश के साथ आवाज और अपील राजधानी के मध्य स्थित सुभाष स्टेडियम मे आ रही थी। मौका था जिला प्रशासन के अधिकारियों और पत्रकारों के बीच क्रिकेट मैच का। इसके साथ साथ कमेंट्री बॉक्स से और मैच के पहले और बाद में 17 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए रायपुर के नागरिकों से मतदान करने की अपील की गई। क्योंकि यह मैच मतदाता जागरूकता के लिए आयोजित की गई थी। 10-10 ओवर का फ्लड लाईट मैच बडा ही रोमांचकारी था। जिसके अंतिम बॉल पर सिक्स मार कर रायपुर प्रेस क्लब की टीम ने मैच जीता। इस अवसर पर प्रेस क्लब अध्यक्ष दामू अंबाडारे और व्यय प्रेक्षक प्रसादराव वाघे, विजयानंद भारती ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने रायपुर के नागरिकों से मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि 17 नवंबर को रायपुर में मतदान होना है। सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि अपने घरों से निकलकर सबसे पहले मतदान करें। अपने परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों को भी प्रेरित करें।इस अवसर पर किया गया टॉस अदभुत था, सिक्के के बदले कार्ड उपयोग किया गयब गया वह अदभुत था। जिसके एक ओर ईवीएम और दूसरी ओर मोर रायपुर का सिम्बॉल था। रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री दामू अंबाडरे और जिला पंचायत के सीईओ श्री अबिनाश मिश्रा के मध्य टॉस हुआ। प्रेस क्लब ने टॉस जीता और बॉलिंग करने का फैसला लिया।

कांग्रेस ने चुनाव आयोग में पूछा शिकायतकर्ता पर क्या कार्यवाही हुई

रायपुर। रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-16 के बीजेपी के प्रत्याशी ओ.पी. चौधरी और उनकी पत्नी अदिति पटेल और सी.आर.पी.एफ. के विरूद्ध की गई आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किये जाने की शिकायत बाबत् के संबंध में आज दिनांक तक क्या कार्यवाही हुई जिसकी जानकारी प्राप्त किये जाने बाबत्। शिकायत में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में हो रहे आसन्न विधानसभा चुनाव में रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-16 के प्रत्याशी ओ.पी. चौधरी और उनकी पत्नी अदिति पटेल के विरूद्ध दिनांक 27.10.2023 एवं 03.11.2023 को शिकायत की गई थी। जिसके पश्चात सी.आर.पी.एफ. के विरूद्ध और ओडिसा के राज्यपाल माननीय रघुवर दास के विरूद्ध आर्दश आचार संहिता का खुला उल्लंघन करने की शिकायत आपके समक्ष की गई थी लेकिन उक्त शिकायत पर आपके द्वारा क्या कार्यवाही हुई इस संबंध में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कामेटी को कोई अवगत नहीं कराया गया है। साथ ही उक्त शिकायत पर आपके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है इस प्रकार से आदर्श आचार संहिता के नियमों का घोर उल्लंघन हो रहा है। महोदय उक्त के संबंध में यदि तत्काल हमें लिखित में जानकारी नहीं दी गई तब ऐसी स्थिति में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों/पदाधिकारियों के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का घेराव एवं धरना प्रदर्शन किया जायेगा जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी।

सीएम बघेल ने छत्तीसगढ़ को किया शर्मसार, तत्काल इस्तीफा देः बृजमोहन

■ महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी के खुलासे के बाद आक्रामक हुए बृजमोहन

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने महादेव एप के प्रमोटर्स द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए जाने पर कहा है कि भूपेश बघेल को मिलने वाले अपराध से अर्जित इस धन के तार कहीं-न-कहीं कांग्रेस आलाकमान से भी जुड़े हो सकते हैं। अगर कांग्रेस नेतृत्व में शर्म बाकी हो तो उसे मुख्यमंत्री बघेल से तुरंत इस्तीफा दिलवाना चाहिए। श्री अग्रवाल ने कहा कि अपराध से अर्जित पैसे का उपयोग चुनाव में करने का पाप प्रदेश कांग्रेस और उसकी भूपेश सरकार कर रही है, इस पर चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। श्री अग्रवाल ने प्रश्न किया कि क्या चुनाव आयोग इस मामले में कांग्रेस को चुनावी प्रक्रिया से अलग करेगा?

भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री श्री अग्रवाल ने शनिवार को एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय आहूत पत्रकार वार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री बघेल ने छत्तीसगढ़ महतारी को शर्मसार और बदनाम करने में कोई कसर

बाकी नहीं रखी है। छत्तीसगढ़ियावाद का पाखंड रचकर छत्तीसगढ़ को बदनाम करने वाले मुख्यमंत्री बघेल को महादेव एप से 508 करोड़ रुपए दिए जाने का खुलासा होना बहुत शर्मनाक है। प्रदेश के लोगों को, युवाओं को सट्टा खिलाकर उन्हें सट्टे के दलदल में धकेलकर उससे लिए गए पैसों को चुनाव में लगाना बेहद आपराधिक षड्यंत्र है, लेकिन मुख्यमंत्री बघेल और कांग्रेस के नेताओं को इससे गुरेज नहीं है। शनिवार को छत्तीसगढ़ पहुँचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी भी इस मामले पर जवाब दें। उन्होंने (श्री अग्रवाल ने) तीन माह पूर्व ही महादेव एप के मामले में दुर्ग-भिलाई का ही कनेक्शन जुड़ने पर यह आशंका व्यक्त की थी कि आगे चलकर इसके तार सत्ता शीर्ष के गिरेबाँ तक पहुँचेंगे जो आज सच साबित हुई है। जब इस मामले की जाँच आगे बढ़ने लगी तो मुख्यमंत्री बघेल ने दिल्ली जाकर कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब तो यह सच भी प्रदेश को बताया जाना चाहिए कि क्या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक महादेव एप की आपराधिक कमाई का हिस्सा पहुँच रहा था?

भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री श्री अग्रवाल ने सवाल किया कि क्या इसीलिए छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही सीबीआई को भूपेश सरकार ने बैन किया था? आखिर क्यों ईडी की कार्रवाई होते ही मुख्यमंत्री बघेल बिना किसी प्रकार की जांच किए सीधे आरोपियों के संरक्षण में खड़े हो जाते हैं। महादेव एप में ईडी के छापों में मुख्यमंत्री के सलाहकार की भूमिका भी सामने आई है।

प्रचार में निकले भाजपा प्रत्याशी पुरंदर का लोगों ने किया आत्मीय स्वागत

■ स्वमेव जुड़कर बढ़ा रहे हैं कारवां,अधिकाधिक मतदान का किया वादा

रायपुर। विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे चुनावी रंग चटख होता जा रहा है। इसी बीच रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा के पक्ष में बने माहौल को और ज्यादा मजबूत करने के लिए चुनाव प्रचार की कमान अब युवाओं की फौज ने भी संभाल ली है। इस युवा सेना का नेतृत्व पुरंदर मिश्रा के ज्येष्ठ सुपुत्र पीयूष मिश्रा कर रहे हैं। बताते चलें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव-2023 में विजय पाने के लिए प्रत्याशियों के प्रचार-प्रसार ने अब काफी जोर पकड़ लिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ प्रत्याशी घर-घर जाकर लोगों मुलाकात कर रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की जा रही है। इधर, रायपुर उत्तर से भाजपा प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा क्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ बनाने का दावा लगातार कर रहे हैं।छत्तीसगढ़ में होने वाले द्वितीय चरण के चुनाव प्रचार के लिए अब 10 दिन ही बचे हैं। इसलिए भाजपा प्रत्याशी के साथ मंडल, वार्ड तथा बूथ स्तर के सैकड़ों कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों सहित महिला मोर्चा व युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। शनिवार को रायपुर उत्तर विस क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा के ज्येष्ठ सुपुत्र पीयूष मिश्रा की अगुवाई में सैकड़ों युवाओं ने साथ क्षेत्र के मुहल्ले और गलियों जाकर जनसंपर्क किया।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.